	3. Dr. S. Chandrasckhur
The National Nutrition Advisory Committee.	ShriK.D^-modaran
The Bharatiya Bhasha Samiti.	1. Shri R. R. Diwakar.
	2. Shri U. S. Dikshit.
The Court of the Aligarh Muslim University.	1. Shri Akbar Ali Khan.

LEAVE OF ABSENCE TO SHRI G. RAMACHANDRAN

MR. CHAIRMAN: I have also to inform Members that the following letter dated the 2nd May, 1966, has been received from Shri G. Ramachandran:

"As my health has suffered a set-back and my doctor has advised me to take a month's rest, I regret my inability to attend the present session of the Rajya Sabha beginning on the 3rd May, 1966.1 request you to be good enough to grant me leave for this session only".

Is it the pleasure of the House that permission be granted to Shri G. Ramachandran for remaining absent from all meetings of the House during the current session *No. hon. Member dissented*

MR. CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

THE APPROPRIATION (NO 2) BILL, 1966- *contd.*

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : सभापति जी, नियोजन मंत्री श्री अशोक मेहता, अपनी विदेश यात्रा से वापस आ गए हैं। वे अपने साथ क्या लाए हैं इसे देश जानना चाहेगा। उनकी यात्रा के दो मुख्य उद्देश्य थे —एक तो 1965 में एड-इंडिया-कन्सोर्टियम ने हमें जो सहायता दी थी और जिसके 285 मिलियन डालर्स अभी मिले नहीं हैं उसे फिर प्राप्त करना और दूसरा उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहायता कितनी होगी इसके बारे में पक्के आश्वासन प्राप्त करना। जहां तक रुकी हुई सहायता के मिलने का सवाल है, आज के पत्रों में वाशिंगटन पोस्ट की यह खबर छपी है कि अमरीका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रुकी हुई सहायता अभी फिर चालू नहीं की जायगी। स्वयं श्री अशोक मेहता कहते हैं कि उनकी यात्रा की सफलता या विफलता को आंकड़ों से नहीं आंका जाना चाहिए। कल पत्राकरों से अनौपचारिक रूप से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि आंकड़े मत देखिए, यह देखिए कि मैं मानसिक मिलन करने में सफल हो गया हूं—यह "मीटिंग आफ माइन्ड्स" का मैं हिन्दी अनुवाद कर रहा हूं। श्री अशोक मेहता का कहना है कि वे जहां जहां गये वहां एक "मानसिक मिलन" कायम करने में सफल हुये। श्री मेहता ने इस सवाल को भी टाल दिया कि जो सहायता भारत-पाकिस्तान-संघर्ष के दिनों में रोकी गई थी क्या उसे भी फिर से वापस दे दिया जायगा।

सभापति जी, बात साफ है कि श्री अशोक मेहता खाली हाथ लौटे हैं। लेकिन मुझे इसके लिये अफसोस नहीं है, शायद मुझे थोड़ा-सा संतोष हो रहा है क्योंकि विदेशों से जो खबरें आ रही हैं, हमें सहायता देने वाले जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि श्री अशोक मेहता तभी भरे हुये हाथ आ सकते थे जब कि आज तक के हमारे सारे आर्थिक चिन्तन, आर्थिक नीतियों, कल के भारत के निर्माण और हमारे सामाजिक उद्देश्यों को अलविदा कह देते। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं शासन के सारे आर्थिक चिन्तन से, उसकी आर्थिक नीतियों से, सहमत हूं। मेरे आधारभूत मतभेद हैं और मैं उन्हें प्रकट करता रहा हूं, लेकिन जिस दिशा में विदेशी हमें ले जाना चाहते हैं वह दिशा और भी खतरनाक है।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि हम आर्थिक संकटों में फंसे हुये हैं और हमारी आर्थिक कठिनाइयों का फायदा उठा कर हमारी नीतियों को प्रभावित करने की योजनाबद्ध कोशिश की जा रही है। कहने के लिये यह काम सलाह देने के नाम पर हो रहा है लेकिन यह सलाह "डिक्टेशन" के रूप में आ रही है और जिन मुसीबतों में हम फंसे हैं शायद उनसे निकलने के लिये हम उस डिक्टेशन को मानने जा रहे हैं ऐसी आशंका मुझे होती है।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता कि विदेशी सहायता बिना बंधन के नहीं मिलती है। विदेशी सहायता के साथ बंधन होते हैं, कोई उपकार की भावना से सहायता नहीं देता है, जो देता है अपने हित में देता है। देखना यह है कि विदेशी सहायता से हमारे हितों पर आंच न आये। कभी बंधन प्रत्यक्ष होते हैं और कभी अप्रत्यक्ष होते हैं, कभी दृश्य होते हैं कभी अदृश्य होते हैं, कभी कम कष्टकर होते हैं कभी अधिक कष्टकर होते हैं। लेकिन विदेशी पूंजी के साथ विदेशी प्रभाव आता है और अब दबाव आ रहे हैं इससे कोई इंकार नहीं कर सकता।

सभापति जी, यह खेद का विषय है कि हम विदेशी पूंजी पर अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं। एक नई बात कही जा रही है कि अगर हमें विदेशी कर्जे से छुटकारा पाना है तो हमें और कर्जा लेना चाहिये, यदि हम विदेशी सहायता से आगे जा कर छूटना चाहते हैं तो हमें और विदेशी सहायता लेनी चाहिये। मुझे याद है पहले अमरीकी गेहूं आया था भंडार बनाने के लिये और अब अमरीकी गेहूं हमारे भोजन का आधार बन गया है; पी० एल० 480 निकट भविष्य में हमारा पीछा छोड़ेगा इसकी सम्भावना नहीं दिखाई देती। विदेशी पूंजी के आने के साथ साथ विदेशी पूंजी पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है। सच्चाई यह है कि हम अधिकाधिक दलदल में फंसते जा रहे हैं। स्पष्ट है कि सब देशों की तुलना में अमेरिका पर हमारी निर्भरता सब से ज्यादा है क्योंकि अमेरिका ने हमें सब से ज्यादा आर्थिक सहायता दी है। अप्रैल 1951 से मार्च 1965 तक हमें कुल 5,172 करोड़ रुपया विदेशों से सहायता के रूप में मिला जिसमें से 2,686 करोड़ रुपया अमेरिका से मिला था, यदि विश्व बैंक का 403 करोड़ रुपया और आई० डी० ए० का 230 करोड़ रुपया जोड़ लिया जाय क्योंकि इसमें भी अमरीकी अंश है तो यह राशि 3,319 करोड़ रुपये हो जाती है। हमें जितनी विदेशी सहायता मिली है उसका 90 फीसदी अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों से आता है।

कुछ दिनों से इस बात की कोशिश हो रही है कि हम अपनी आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करें। विरोधी दल में बैठे हुये सदस्य भी इस तरह की मांग करते रहे हैं लेकिन जब यह मांग वाशिंगटन से, बौन से, लन्दन से आती है तो हमारे हृदय में आशंकायें पैदा होती हैं। सीधे सीधे अमेरिका द्वारा कहने के बजाय अब विश्व बैंक ज्यादा से ज्यादा तसवीर में लाया जा रहा है और जो बातें अमेरिका कहना चाहता है वह विश्व बैंक से कही जा रही हैं...

श्री व्रजकिशोर प्रसाद सिंह (बिहार) : आपको तो खुशी होनी चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति जी, मैं आपका ध्यान श्री जान फेनी के एक लेख की ओर खींचना चाहता हूं। मैं उनके शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं। "पिछले वर्ष बैंक ने भारत की आर्थिक योजनाओं की आलोचना की। उधर अमेरिका ने भी भारत की आर्थिक उन्नति के विषय में दुबारा सोचने की जरूरत समझी, विशेषतया भारत के कृषि उत्पादन के विषय में। अतः अमेरिका और विश्व बैंक दोनों का दृष्टिकोण मेल खा गया। अतः अमरीका प्रशासन की धारणा है कि भारत में जिन आर्थिक सुधारों को वह ठीक समझता है उन सुधारों को विश्व बैंक के जरिये भारत के सामने रखा जाय।" ये सुधार क्या हैं? यदि सुधार सही दिशा में हों, हमारी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हों तो मैं उन सुधारों को केवल इस आधार पर ठुकराने के पक्ष में नहीं हूं कि वह सुधार अमेरिका से आते हैं। लेकिन यदि वे सुधार जरूरी हैं तो फिर वह वहां से आयें इस बात के लिये सरकार को रुकना नहीं चाहिये, दूरदृष्टि से पहले ही उन सुधारों को कार्यान्वित करना चाहिये था। लेकिन एक नई परिस्थिति पैदा हो रही है। अब हमसे कहा जा रहा है कि

हम इम्पोर्ट कंट्रोल्स को ढीला करें, आयात पर हमने जो नियंत्रण लगा रखे हैं उनको ढीला करें, रुपये का अवमूल्यन करें, डिवैल्युएशन करें, देशी और विदेशी पूंजी को अपने देश में ज्यादा सुविधायें दें और भारतीय खेती का यंत्रीकरण करें, परिवार नियोजन करें, नये नये ढंग अपनायें। मेरा निवेदन है कि आयात पर नियंत्रण को ढीला करना या रुपये का अवमूल्यन करना यह खतरे से खाली नहीं है। पहले ही हम अपने कलकारखाने को चलाने के लिये विदेशों से कच्चे माल पर निर्भर हैं और उस कच्चे माल के आयात के लिये हमें विदेशी मुद्रा चाहिये जिसके लिये भी हम विदेशों पर निर्भर हैं। अब अगर हम आयात बढ़ायेंगे तो हमारी निर्भरता और बढ़ेगी जो आर्थिक विकास के मार्ग में नया रोड़ा खड़ा करेगी। आज की स्थिति में रुपये का अवमूल्यन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम एक बड़ा खतरा मोल लेंगे अगर हम रुपये की कीमत घटाने का निर्णय लेंगे। लेकिन विदेशों से इस बारे में दबाव पड़ रहा है और देश में भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो रुपये का मूल्य घटाने की वकालत कर रहे हैं।

सभापति जी, शर्तें केवल आर्थिक नहीं हैं, राजनीतिक भी हैं। जो विदेशी हमें सहायता देना चाहते हैं वह हमसे गारंटी मांगते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मित्रता से रहेंगे। क्या मित्रता केवल एकतरफा हो सकती है? अगर पाकिस्तान शत्रुता के लिये आमादा है तो अच्छे सम्बन्ध कैसे होंगे? लेकिन हम पर दबाव डाला जा रहा है और भारत-पाकिस्तान-संघर्ष के बाद यह दबाव और बढ़ा है कि अगर भारत और पाकिस्तान लड़ते रहेंगे तो हम सहायता नहीं देंगे। लेकिन जिस पाकिस्तान ने लड़ाई शुरू की, जिसने इस भूखंड में युद्ध की चिनगारी को भड़काया, उसे और हमें वह एक तराजू पर रखना चाहते हैं, मानो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक पैरिटी हो गई है। युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया किन्तु वे पाकिस्तान को दंड देने को तैयार नहीं हैं, उसे सैनिक सहायता से और आर्थिक सहायता से वंचित करने को तैयार नहीं है। इसके विपरीत हम से मांग करते हैं कि हम अच्छे आचरण की गारंटी दें। ऐसी एक तरफा गारंटी नहीं दी जा सकती है। लेकिन हमारी निर्भरता उनके ऊपर इतनी बढ़ गई है कि हम इस मामले में थोड़ा देश को खतरे में डालकर भी शान्ति की भाषा बोलने के लिए तत्पर नजर आते हैं।

सभापति जी, यह भी सुझाव आया है कि भारत पाक के मिलेजुले प्रोजेक्ट होने चाहियें और यह सुझाव भी उन्हीं सूत्रों से आया है। भारत और पाकिस्तान मिलाजुला काम करें और संयुक्त परियोजनाएं बनायें। कौनसी परियोजनाएं मिली-जुली बन सकती हैं? क्या आज की स्थिति में यह व्यावहारिक सुझाव है? जहां मित्रता नहीं है, वहां सहयोग कैसे हो सकता है? यह कहना भी गलत है कि अगर आर्थिक क्षेत्र में हम मिलकर काम करेंगे तो हमारी शत्रुता खत्म हो जायेगी। यह तो घोड़े के आगे गाड़ी जोतनेवाली बात है। अगर मित्रता हो, नीयत साफ हो, तो हम आर्थिक सहयोग के सौ रास्ते निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नीयत साफ नहीं है तो "इंडो पाकिस्तान ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट" की बात नये झगड़े को जन्म देगी और वह नया विवाद खड़ा करेगी। इससे तनाव बढ़ेगा। सबसे भयंकर बात यह होगी कि थर्ड पार्टी को दोनों के बीच में बंदर बांट करने का मौका मिलेगा और इस भूखंड में उनकी उपस्थिति जरूरी हो जायेगी। मुझे आश्चर्य है कि श्री अशोक मेहता ने ऐसा क्यों कहा कि हम "ज्वाइन्ट इंडो पाक प्रोजेक्ट" के बारे में विचार करने के लिए तैयार हैं। क्या केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस तरह का कोई नीति संबंध निर्णय ले लिया है? अगर ले लिया है, तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस सुझाव के सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है। किस तरह का आर्थिक सहयोग हो, इसके लिए पहले वातावरण बनाना जरूरी है। ताशकंद घोषणा के बाद पाकिस्तान ने जो रवैया अपनाया है उससे यह आशा नहीं

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

बंधती है कि पाकिस्तान हमारे साथ शांति के साथ रहना चाहता है। इस संदर्भ में संयुक्त परियोजनाओं की बात करना आसमान में उड़ने के बराबर है।

एक और प्रश्न की चर्चा हुई है और वह है "इंडो अमेरिकन एजूकेशन फाउन्डेशन" जब इसकी चर्चा पहले शुरू हुई थी तो मेरे मित्र श्री भूपेश गुप्त जो इस समय रूस की यात्रा पर गये हैं, उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया था। मैं उस समय चुप रहा था क्योंकि हम सोचने के लिए, विचार करने के लिए समय चाहते थे। अमेरिका से आने वाली हर एक बात बुरी है, इसमें मेरा विश्वास नहीं है। रूस से आने-वाली हर एक बात अच्छी है मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन मेरा दल एजूकेशन फाउन्डेशन के बारे में गम्भीरता से विचार करने के बाद इस परिणाम पर पहुंचा है कि भारत सरकार को इस फाउन्डेशन के बारे में मूलत: पुन: विचार करना चाहिये। पी० एल० 480 में दिये गये गेहूं के बदले जो 150 करोड़ रुपये भारत में जमा हैं और जिस पर 6 करोड़ के करीब ब्याज के रूप में आने वाले हैं, उसको भारत के हित में लगाने के अनेक मार्ग हो सकते हैं। वह रुपया शिक्षा मंत्रालय को दिया जा सकता है जो शिक्षा के विकास और प्रसार में लगाया जा सकता है। वह रुपया यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन को सौंपा जा सकता है जिसे ऊंची शिक्षा को बढ़ाने के काम में लाया जा सकता है। लेकिन इस तरह का नया फाउन्डे-शन बनाने की क्या जरूरत है कौन सी आवश्य-कता आ पड़ी है? इस फाउन्डेशन के क्षेत्र में क्या होगा, इसके बारे में पढ़ पढ़ कर बड़ी चिन्ता होती है। अमेरिकी पत्र क्या कह रहे हैं, अमेरिकी सूत्र क्या कह रहे हैं, मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात यह है, वह मैं अंग्रेजी में उद्धत कर रहा हूं :

"*To* set up a centre tor eaucuuonai cooperation in the U. S. Department of Education to give direction to the j Foundation."

फाउन्डेशन का निदश अमारका शिक्षा मत्रालय द्वारा होगा। श्री चागला जैसा कहते हैं यह संस्थान वैसा नहीं है। कम से कम फाउन्डेशन में जो अमेरिकी सदस्य होंगे वे अपना निर्देश, अपना आदेश, अमेरिका के शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त करेंगे। दूसरी बात :

"To stimulate new programmes in international studies for elementary and Secondary schools"

अभी तक समझा जा रहा था कि विश्वविद्यालय के स्तर पर, कालेज के स्तर पर सहायता देने का काम यह फाउन्डेशन करेगा। मगर फाउन्डेशन के विचारों को आगे बढ़ानेवाले, उसके लिए अपनी पूंजी देनेवाले किस दिशा में सोच रहे हैं, यह जानना जरूरी है। वह हमारे प्राइमेरी और इलिमेन्टरी स्कूलों को उस फाउन्डेशन की परिधि में लाना चाहते हैं।

तीसरी बात यह है :

"To build 1,000 schools through schoc! partnerships."

यदि फाउन्डेशन का यह क्षेत्र होने वाला है तब तो हम फाउन्डेशन का मूलत: विरोध करने के लिए विवश होंगे। शिक्षा बड़ा मार्मिक स्थल है और शिक्षा का राष्ट्र के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हम विदेशी अनु-भवों से, ज्ञान और विज्ञान से, लाभ उठायें अपनी आवश्यकता के अनुरूप, अपनी आकांक्षा-ओं के अनुसार, अपनी प्रकृति और प्रतिभा का विचार करके हम अपनी शिक्षा पद्धति का पुनर्गठन करें, विकास करें और विस्तार करें। इसमें मतभेद नहीं हो सकता है। लेकिन हमारी शिक्षा इतनी विदेशी प्रभाव में चली जाय, यह देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। 6 करोड़ रुपया कम राशि नहीं है। यह रुपया जब बांटा जायेगा और बांटते समय किसे दिया जा रहा है यह देखा जायेगा तो रुपया बोलेगा, पैसा अपना प्रभाव प्रकट करेगा। आज जब देश में राष्ट्रीयता का भाव उग्र नहीं है, जब देशभक्ति हरएक नागरिक का धर्म नहीं है, जब विदेशी प्रभाव में सारा राष्ट्र विभ्रान्त होता दिखाई देता है, तो इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी किसी फाउन्डेशन के हाथ में रखना खतरनाक है कि कहीं हमारी शिक्षा का सारा

ढांचा ही न लड़खड़ा जाये। फाउन्डेशन के द्वारा अमेरिका से प्रोफेसर आयेंगे, यहां से प्रोफेसर भेजे जायेंगे और भारतीय विद्यार्थियों को आकृष्ट करने का कार्यक्रम बनेगा। आज भी कुछ संस्थाएं हैं जो इस तरह का कार्यक्रम कर रही हैं। वे संस्थाएं यह कार्यक्रम कर सकती है, लेकिन अलग से कोई फाउन्डेशन बनाने की मुझे आवश्यकता दिखाई नहीं देती है।

सभापति जी, कहा जाता है कि फाउन्डेशन का चेयरमैन भारतीय होगा। सदस्य भारतीय और अमेरिकी बराबर होंगे। यदि एग्जीक्यूटिव आफसर अमेरिकी होगा तो चेयरमैन भारतीय होगा। यह संख्या का सवाल नहीं है। गोरी चमड़ी आज भी देश में जादू चलाती है। केवल कनाट प्लेसों की दुकानों पर ही नहीं, सरकारी दफ्तरों में भी जो भारतीय नागरिक पहले से आये होते हैं उनकी उपेक्षा करके गोरी चमड़ी वालों को प्राथमिकता दी जाती है। अभी हम विदेशी प्रभाव से इतने मुक्त नहीं हो सकते हैं। सदस्य, बराबर होते हुए भी, वहां किस का प्रभाव चलेगा, इसके बारे में हमें आशंका है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस फाउन्डेशन के सवाल पर फिर से विचार करे।

सभापति जी, आज हमारा देश एक मोड़ पर खड़ा है और भारत का भविष्य अंतिम रूप लेने जा रहा है। शायद जितनी संकटपूर्ण स्थिति आज है उतनी कभी पैदा नहीं हुई। चीन और पाकिस्तान का गठबन्धन बढ़ा है। हमारी सुरक्षा के लिये खतरा हुआ है। लेकिन ताशकन्द घोषणा के बाद देश में एक असावधानी आई है, शिथिलता का भाव आया है। आर्थिक संकट तो बड़ा गहरा है। हर क्षेत्र में एक मन्दी है। 30 फीसदी मूल्य बढ़े हैं। 40 लाख बेकारों को हम काम नहीं दे सके हैं जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत काम पाने के अधिकारी थे। अन्न के मोरचे पर भी हम विफल हुये हैं। इस संकटकाल में से उबरने का रास्ता क्या है? विदेशी सहायता तात्कालिक असर दिखा सकती है। उसे पी कर हम में थोड़ी सी चेतना आ सकती है। वह आज की मन्दी से शायद हमें उबार सकती है मगर वह भविष्य के लिये नये गड्ढे खोदेगी। मैं सिद्धान्ततः विदेशी सहायता का विरोधी नहीं हूं। मगर जिस मात्रा में विदेशी सहायता आ रही है, जिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शर्तों के साथ आ रही है, उसे लेने का देश में जैसा वातावरण बनाया जा रहा है, वह खतरे की घंटी है और कोई भी देशभक्त उस खतरे की घंटी को सुनने से इन्कार नहीं कर सकता।

सभापति जी, मुझे शिकायत है कि सरकार इस संकट में से देश को निकालने के लिये कोई मौलिक चिंतन करने को तैयार नहीं है। योजना आयोग किसी क्रांतिकारी परिवर्तन के लिये प्रस्तुत नहीं है। सरकार अपने नारों के जाल में बन्दी हो गई है। योजना आयोग शब्दों के पीछे भागता है। हमें विशेषज्ञों की आवश्यकता है। मगर अंतिम रूप से भारत का भविष्य तब बनेगा जब देश की 47 करोड़ जनता को खड़ा किया जा सकेगा, उसकी आंखों में नये भारत का सपना भरा जा सकेगा, उसकी भुजाओं के लिये काम जुटाया जा सकेगा। आर्थिक योजनाओं, आर्थिक समस्याओं की ओर देखने का हमारा दृष्टिकोण ऐसा है जो लोगों में निराशा पैदा कर रहा है, जो भविष्य के लिये आशंका पैदा कर रहा है। मेरी मांग है कि योजना आयोग का पुनर्गठन होना चाहिये। उसके सदस्यों में उसके काम करने के ढंग में और उसके दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन जरूरी है। धीरे धीरे योजना आयोग की शक्ति बढ़ती जा रही है, मगर उस मात्रा में योजना आयोग अपने दायित्वों का पालन नहीं कर पा रहा है। मैं यह भी चाहता हूं कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं में हमने क्या लक्ष्य रखे थे, उनकी कितनी उपलब्धि हुई, हमने क्या खोया, क्या पाया, हमारी आर्थिक स्थिति में कहां तनाव और खिंचाव पैदा हो रहा है, इस सब की जांच के लिये एक स्वतंत्र संगठन होना चाहिये। इवैल्युएशन के लिये, मूल्यांकन के लिये एक पृथक संगठन होना चाहिये। यह काम योजना आयोग पर नहीं

[श्री अटल विहारी वाजपेयी]

छोड़ा जा सकता। योजना आयोग योजना बनाता भी है, उसको कार्यान्वित करने में सहायता पहुंचाता है, फिर उसका मूल्यांकन भी करता है। इसमें योजना आयोग न तो अपने साथ न्याय कर सकता है और न देश के साथ न्याय कर सकता है। हमें उच्चाधिकार सम्पन्न एक स्वतंत्र संगठन की जरूरत है जो आज तक के आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों का ठीक ठीक मूल्यांकन कर सके और भविष्य के सम्बन्ध में सुझाव दे सके।

सभापति जी, यह भी जरूरी है कि आज जो संकट की परिस्थिति खड़ी है उसमें से निकलने के लिये शासन और विरोधी दल अपना दृष्टिकोण बदलें। मैंने उस दिन कहा था कि क्या देश में यह विवाद जरूरी है कि भूख से लोग मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं या यह जरूरी है कि जो भूख से मर रहे हैं या कल मरने वाले हैं या जुलाई और अगस्त में जिनकी हालत और बिगड़ने वाली है उनको बचाने के लिये मिल कर, बैठ कर कोई रास्ता निकाला जाय? एक जगह अन्न बरबाद हो रहा है और दूसरी जगह लोगों को खाने के लिये अन्न नहीं मिल रहा है। सरकार चुनाव की चिन्ता करती है। विरोधी दल भी चुनाव की चिंता से मुक्त नहीं हैं। मगर क्या इस संकटकाल में हम इतना भी ऊंचे नहीं उठ सकते कि कम से कम लोगों को भुखमरी से बचाने के लिये सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर एक हो कर बैठें, कोई मार्ग निकालें। मुझे कहीं भी तस्वीर में स्वयंसेवी संगठन नहीं दिखाई देते। उड़ीसा में लोग भूख से मर रहे हैं, यह तो खबर आई। मगर मरने वालों को कोई अन्न बांट रहा हो, कोई बच्चों को दूध दे रहा हो, इसकी खबरें आना बाकी हैं। क्या हो गया है इस देश को? कहां गये हमारे स्वयंसेवी संगठन? क्या सब सरकार के ऊपर ही निर्भर रहेगा? राजनीति इतनी विकृत हो जायगी, इतनी दूषित हो जायगी, यह तो कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। मगर जब तक शासन अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, इस परिस्थिति में से निकला नहीं जा सकता।

सभापति जी, मैं एक बात कह कर समाप्त कर दूंगा। श्री सुब्रह्मण्यम उड़ीसा की यात्रा पर गये। क्या वे अपने साथ उड़ीसा के विरोधी दलों के संसद सदस्यों को नहीं ले जा सकते थे? प्रधान मंत्री उड़ीसा जाने वाली हैं। क्या वे श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी और श्री लोकनाथ मिश्र को अपने साथ उड़ीसा की यात्रा के लिये आमंत्रित नहीं कर सकतीं? क्या विरोधी दलों को उनसे जा कर कहना चाहिये कि हम भी आपके साथ चलेंगे? क्या वे इतना ऊंचे नहीं उठ सकतीं? क्या इस सरकार के मंत्री संकटकाल में इतने बड़प्पन का परिचय नहीं दे सकते कि उड़ीसा में जो परिस्थिति पैदा हो गई है उसका निराकरण करने के लिये सब को साथ ले कर चलें? अगर नहीं चल सकते तो देश का दुर्भाग्य हमारे सामने है और उस पर विजय प्राप्त करना कठिन होगा। धन्यवाद।

SHRI R. T. PARTHASARATHI (Madras): Mr. Chairman, Sir, it is my proud privilege to rise to say a few words in support of the Appropriation Bill and I am happy that it happens to be my first speech in Parliament. I support the main provisions of this Bill in principle and in all its details.

As I was going through the Demands for Grants of the Home Ministry, the Ministry of Education and for administration of justice I was led to think that there is one cardinal factor that contributes vitally to the progress of the nation and that is national integration. When we were under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru we did not very much think that there would be fissiparous tendencies raising their heads in a united India; that there will be any danger to the concept of our unity, to the concept that we are one nation. We were one nation fighting for freedom and in the post freedom era also and we thought we were one nation but we have witnessed separatist tendencies and secessionist movements which were deliberately cutting at the root of Indian unity. What is the duty of the Gjvernmentat this stage? It is the duty of the Government to nip these separatists tendencies in the bud and crush the secessionist movements. If any legislation is necessary, that should come here and new.

Mr. Chairman, there is a movement in the south and there is a movement in Naga land, encouraging separatist tendencies. It is essential that we should formulate a constitutional amendment to ban these separatist tendencies if we are to live as a glorious nation, worthy of the name of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi Mr. Chairman, I would very respectfully submit that separatist tendencies are seditious in nature and a deliberate fostering of an all India patriotism should be nursed, encouraged and fostered if we are to live in the larger context of the world as a great nation. The Ministry of Education which has asked for a grant of Rs. 46 -4 crores can give us a great help on one aspect of this question. Mr. Chairman, I may be asked as to what the Ministry of Education can do in this matter. The future of the country rests on our younger generation, on the student population, on our school-going children and all those who are in the universities. If only the Education Ministry would have a greater control on the whole of India, things would be better. I am not joining the issue whether education should be a Central subject or a Concurrent subject. Just as the Food and Agriculture Ministry have their own grip on all the States of India, it is the duty of the Education Ministry to extend its tentacles on the States which, are in a large measure, going towards regionalisation based on their own language. We find that the language issue has been knocking almost at the door of every home. In this respect I would very much like the Education Ministry to tell the State Ministries that they can have by all means the regional medium in the various schools and colleges, but it is the duty, in the larger context of India, of the Union Education Ministry to open in every State or in every region a regional Central University with English as the sole medium, with a view to developing our science and technology. The great services of Pandit Jawaharlal Nehru for the development of science and technology and higher mathematics, the great services rendered towards bringing up the younger generation will be wasted, if we are going to give a go-by to English, especially in relation to science and technology. My humble submission to you, Mr. Chairman, is that it is too early to think of giving up English, but I am not one of those who very blindly say "Hindi *marjai".*

not say that. If I say that, I am not an Indian at all. But, on the other hand, the language issue touches the very heart and mind of every Indian citizen. If only hon. Members had correct reports of what happened in the various parts of South India and particularly in Tamilnad, as a result of what they call the anti-Hindi movement, they would have known the pulse of the people. After all we are a democracy. We have given unto ourselves a Constitution of our own making to suit our genius. I would very respectfully appeal to you *to* see that their feelings are not wounded. I would appeal to the Hindi protagonists to view the entire question in a benevolent manner and with a balanced judgment. If only they do that, there will be no rubbing of the non-Hindi people on the wrong side. I have stated earlier that I am one of those who think and are convinced that in the future India, if not today, may be 30 years or 50 years later, Hindi is bound to replace English as the official language, as the link language, but the immediate problem is not what is going to happen 50 years later or 30 years later. The immediate problem that we have got is to tell the younger generation that their education is safe in the Government's hands, that the Government of India would not do anything which would harm their interests and as such I feel and I am convinced that the only way of doing that is to carry out in letter and spirit Pandit Jawaharlal Nehru's assurance to the non-Hindi speaking people. It may be in the form of a constitutional amendment. It may be in the form of a legislation before Parliament. Whatever it be, it is a very essential thing,from the point of view of public interest, from the point of view of the ruling Party. As the general elections are in the offing, we must show unhesitatingly and in an unequivocal manner that something is being done and something has been done to safeguard the interests of the non-Hindi speaking people.

Mr. Chairman, it is also my duty to refer to one or two other aspects of our national economy. We have been concentrating rather too much on very big projects, whereas the Indian economy is absolutely suitable for medium-sized and small scale projects. May I ask very respectfully the Government of India as to what they have done for the Salem steel plant, a project that they had promised through the then

[Shri R. T. Parthasarathy]

Finance Minister, Mr. T. T. Krishnamachari, twelve years ago? They had promised that a medium-sized steel plant with the help of Neyveli lignite would be coming up. Why today the Salem steel plant—when everything has been done—has been halted, for the purpose that it is being equated, may I say, with those of Hospet and Visakhapatnam ? If we do not follow up a medium sized plant like that, which is a small, economic unit by itself, it will be to the detriment of the nation as a whole. I would very respectfully, Sir, request the Government of India to make an announcement that the Salem plant has been sanctioned and without any hesitation they should do so.

Mr. Chairman, it is my duty to say a word or two and I am very sorry to say that, about an unfortunate reference, which my learned friend from Madras, who belongs to the Swatantra Party, made, when he initiated this debate. This is not a political platform where we should express our differences of views. The hon. Member referred to the Congress President and very unfortunately he attacked him and dishonoured the convention that when the other person is not in this House it is better that we do not refer to his speeches or his actions. I would only say that I was present at the meeting, the subject-matter that the hon. Member put up before the House. The Con-, gress President never spoke in that manner and I would very respectfully say that the hon. Member carried too much of his personal vendetta against the Congress President . . .

SHRI S. S. MARISWAMY (Madras): Mr. Chairman, this is his maiden speech. So, I do not interrupt him, but what he says is not correct.

SHRI R. T. PARTHASARATHY: Is it not the convention that maiden speeches should not be interrupted in Parliament?

SHRI S. S. MARISWAMY: That is the convention of this House. You kindly make yourself acquainted with the conventions here.

SHRI R. T. PARTHASARATHY : It was equally unfortunate that the hon. Member said, rather misled the House, I would very courageously put it that way, that the portrait of no South Indian adorns Parliament House. I was the Secretary of the Committee which presented a portrait of that great stalwart, independent Indian, C. Vijaraghavachariar, which adorns Parliament, and which was unveiled by Dr. Rajendra Prasad, the late President, in the Central Hall of Parliament. If we, who hail from South India, have any grievance, we could take it up with the Chairman of this House or the Speaker of the Lok Sabha or with the Prime Minister and see that the portrait is put up in the Central Hall. To say that no South Indian's portrait is there . . .

SHRI S. S. MARISWAMY: I would again say that the portrait of C. Vijaraghavachariar, who was his grandfather, is not in the Central Hall. It is in the Library.

SHRI R. T. PARTHASARATHY: I am sorry to say it. It is in the Committee Room, where it is adorning. It is not in the Library.

Mr. Chairman, the other aspect which my learned friend put forward—he did not say in so many words by himself—but he put it in the words of the South Indian leader, Dravida Kazhagam leader, in whose name he said, that he is reported to have referred to our distinguished Prime Minister as that Kashmiri Brahmin girl. May I ask: Is there anybody today who enjoys the confidence of the whole country, who is the representative of the nation, more than Mrs. Indira Gandhi?

SHRI S. S. MARISWAMY: I want to give an explanation. I said Periyar Ramaswamy Naicker was going about the country, saying that our Prime Minister—for whom I said I have got the utmost regard—was after alia Brahmin girl. I said Mr. Kamaraj was following the footsteps of Periyar Ramaswamy Naicker. Now he goes at the Brahmins and tomorrow Kamaraj himself will turn against our Prime Minister. That is what I said, I have never said anything else.

MR. CHAIRMAN: You best avoid these references.

SHRI R. T. PARTHASARATHY: I am about to conclude. On this occasion I would like to pay a tribute to Mrs. Indira Gandhi, to the qualities of her leadership, that she is the representative of Indian womanhood and she is a great gift of her

father, Prime Minister Jawaharlal Nehru, to this nation.

SHRI S. S. MARISWAMY: Kindly tell this to Mr. Kamaraj and to Periyar Ramaswamy Naicker.

SHRI R. T. PARTHASARATHY: Mr. Chairman, I feel I have come to the brink of my time, and I would like to conclude by an appeal to this House that there has been a very important matter, a major issue which has been engaging the attention of the Members of both Houses of Parliament, that is, how to establish a convention on the question of scrutiny of the grants of the respective Houses.

MR. CHAIRMAN: It is not necessary to refer to that at this stage.

SHRI R. T. PARTHASARATHY: I am constrained to say that this major issue is there because the other House thinks that we have no financial powers, whereas we form part of the sovereign body individually and together, and that is why a healthy convention should be established. Supposing, for example the Lok Sabha which is alleged to have the financial powers should vote out the judiciary, if they would not vote the grant for the Supreme Court, then the whole Constitution is nullified. That is the reason why I say that a healthy convention should be observed in both the Houses and respect for law and legality and procedure should be maintained, as ultimately both Houses form part of the sovereign body, that is, the entire sovereignty vests in the two Houses of Parliament.

I would conclude by saying that in this difficult crisis in which our Prime Minister is shouldering a great responsibility, it is the duty of all Members of the House to give constructive support, solid support towards the betterment of the people as a whole and raise India to a very high status following the path laid by the eminent patriarchs of the nation like Mahatma Gandhi, Lokamanya Tilak, Vijayaraghavachariar and our illustrious leader, Jawaharlal Nehru, and make India united, strong and a regenerated India.

شری عبدالغنی (پنجاب) : چیرمین صاحب - میں اپروپریشن بل کا سواگت کرتا ہوں - مجھے خوشی ہے کہ سرکار اپنی ضروریات کو ہاؤس کے سامنے لائی ہے - میں شری راج نرائن سنگھ جی کے ساتھ متفق نہیں ہوں کہ اس سرکار کو اس کی ترٹیوں کے کارن کوئی پیسہ نہیں دینا چاہئے، اس کا کوئی بل پاس نہیں کرنا چاہئے -

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

لیکن جہاں میں اس کا سواگت کرتا ہوں وہاں کچھ گذارشات ڈپٹی چیرمین کے ذریعہ سرکار کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں - سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مرحوم پنڈت جواہرلال نہرو کے نقش قدم پر چل رہی ہے لیکن اس کا عمل اس کے خلاف ہے - پنڈت جواہرلال نہرو نے اس مشہور حب وطن کو جسے شیر ہند بھی کہا گیا ، شیر کشمیر بھی کہا گیا ، شیخ عبداللہ کو ، اتنی عزت بخشی تھی رہا کرکے کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ کشمیر کی پرابلم جو ہے ، جو آئے دن تلخ ہوتا جاتا ہے ، اس کو کسی طرح سے حل کیا جائے - اختلاف رائے ہو سکتا ہے-- کل ڈھیا بھائی پٹیل طاقت میں آ سکتے ہیں اور میری بہن اندرا جی اپوزیشن میں جا سکتی ہیں لیکن اس کے معنی یہ کہاں ہیں کہ اگر پنڈت جواہرلال نہرو نے کوئی بات کی تھی اور اٹھائی تھی کہ کسی طرح پاکستان اور ہندوستان کے درمیان

تو میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے لیکن ہم کہیں کہ ہم کشمیر کے متعلق کوئی بات نہیں کرینگے تو اسے میں نہیں سمجھ سکتا۔ آج بھی اس مسئلہ کا حل، تاکہ ملک پر جو کروڑھا، ارب‌ھا روپئے کا بوجھ پاکستان کی لڑائی میں پڑا اور ہمارے جو ترقی کے تعمیری کام ہیں وہ رکھے ، اس کا کوئی نہ کوئی اپائے ہو ۔

میں اس کے ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایمرجنسی کے پردہ میں آپ نے بے شمار بہنوں بھائیوں کو جیل میں رکھا ہے ۔ کوئی ڈیموکریسی کی علم بردار سرکار غیر متعین وقت کے لئے بغیر مقدمہ چلائے ان لوگوں کو جیل میں رکھے جنہوں نے کہ ان سے زیادہ انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے قید کاٹی ہے ٹھیک نہیں ہے ۔ ان گدیوں پر بیٹھنے والے کئی ایسے ہیں جنہوں نے گاندھی جی کی شکل نہیں دیکھی ، کئی ایسے ہیں جنہوں نے انگریز کے راج میں کانگریس کا نام نہیں لیا اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے دیش کی آزادی کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھایا ۔ لیکن یہ سب محب وطن بن کر ، کیوں کہ طاقت ان کے ہاتھ میں ہے ، ایسا کر رہے ہیں ۔ میں مانتا ہوں کہ اگر کوئی دیش دروہی ہو تو اس پر

[شری عبدالغنی]

جو ایک ہی جھگڑا ہے اور وہ کشمیر کا ہے اسے سالو (Solve) کیا جائے اس کا جواب یہ دیا جائے کہ سرکار شیخ عبداللہ کو جیل میں رکھے ، نظر بندی کی حالت میں رکھے اور اس سے یہ مدد نہ لے کہ کشمیر کا مسلہ حل ہو ۔ کون نہیں جانتا کہ کشمیر کی وجہہ سے ہی ابھی ابھی جو آخری جنگ ہوئی اور جس میں ہمارے ہندوستانی وجئی ہوئے پاکستان کے ساتھ ، اس کا کارن کشمیر تھا ۔ یا تو سرکار آئے دن یہ نہ کہے کہ وہ پنڈت جواہر لال نہرو کے قدموں پر چلنا چاہتی ہے اور اگر کہتی ہے کہ چلنا چاہتی ہے تو اسے شیخ عبداللہ کو رہا کرنا چاہئے اور شیخ عبداللہ کے ذریعہ کشمیر کے مسلہ کو پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کے لئے نبٹانا چاہئے ۔ اس کو نبٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان اپنی ضد سے باز آئے ۔ وہ جانتا ہے کہ کشمیر ہندوستان کا ہے اس نے اس کے ایک حصہ پر قبضہ کر رکھا ہے ۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، ڈپٹی چیر مین صاحبہ ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہاں سے شری لال بہادر شاشتری چلے تھے تو سب نے اپنی دعائیں دی تھیں اور میں نے دعا دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر جنرل ایوب یہ کہیں کہ میں کشمیر کے متعلق بات نہیں کروں گا

شری عبدالغنی : میرے بھائی اکبر علی یہ کہہ رہے ہیں لیکن ایک مراٹھی بھی یہ قبول نہیں کرتا کہ وہ تامل کے نیچے چلا جائے یا ایک تامل یہ قبول نہیں کرتا کہ وہ آندھرا یا مہاراشٹر کے نیچے چلا جائے - تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو چھوٹے فرق آپ پیدا کر رہے ہیں - میں بچپن میں پڑھا کرتا تھا مہاراجہ ادھی‌راج چکرورتی مہاراج چھہ گاؤں کے راجہ ہوا کرتے تھے - تو آج چپہ چپہ پر نئی نئی اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں اور بنتی جا رہی ہیں - یہ جو ٹینڈینسی ہے وہ دیش کو کہاں لئے جا رہی ہے - آپ ارب ہا روپیہ منظور کرائیے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کیوں کہ کوئی سرکار بنا روپیئے کے نہیں چل سکتی - میں نے اپنی زندگی میں بجٹ کی مخالفت نہیں کی - اس لئے نہیں کی کہ کوئی بھی سرکار ہو - اپوزیشن کی ہو یا موجودہ کانگریس کی ہو بغیر اس کے نہیں چل سکتی لیکن ہماری ٹینڈینسی کس طرف چل رہی ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گھروندے آپ بنانے جا رہے ہیں اور اس کو آپ لینگویج کا بہانہ دیتے ہیں - میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں آج سرکار اس بات کی طرف وچار نہیں کرتی کہ اپنے دیش کی حالت کو سدھارنے کے لئے ، نیشنل انٹیگریشن ، جسے آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان ایک ہے ہر ہندوستانی برابر مقدمہ چلاؤ نہ کہ یہ کہ اس پردہ میں کیرل کے تمام لوگوں کو ڈیموکریسی سے محروم کر دو یہ سرکار جو ڈیموکریسی کی علمبردار ہے اپنے ہاتھ میں ایسا ڈنڈا رکھنا چاہتی ہے جس سے ڈیموکریسی کا گلا گھونٹا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنڈت جواہرلال نہرو کے نقش قدم پر نہیں چلتی - میں اس بات پر بھی حیران ہوتا ہوں کہ آخیر ڈیموکریسی کے معنی کیا یہ ہیں کہ اگر شنکر جی کامیاب ہو جائیں تب تو کیرل میں ڈیموکریسی چلے گی اور اگر اپوزیشن والے جیت جائیں تو کیرل میں ڈیمو کریسی نہیں چلے گی - یہ باتیں جو ہیں کسی سرکار کو سجتی نہیں ہیں - اس سے سرکار کی طاقت بنتی نہیں ہے -

جہاں میں نے یہ کہا وہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ناگا لینڈ کا قصہ ہوا - یہ جو میزو کا قصہ ہوا یہ آئے دن مہاراشٹر اور میسور کی جنگ ہو اور آندھرا اور تامل کی جنگ ہو . . .

شری اکبر علی خان (آندھرا پردیش) : آندھرا اور تامل میں کوئی جنگ نہیں ہے -

ہو اور ہم مل جل کر اپنے دیش کی دوسری یوجناؤں کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں ۔

مجھے ایک بات کہنی ہے اور وہ یہ ہے کہ بد قسمتی سے اس وقت ایڈمنسٹریشن جو گنگا اور جمنا کی طرح پوتر ہوتا ہے ، جس میں چھوٹے بڑے ملازم سب ہوتے ہیں ، اس میں کوئی آفیسر کہلاتا ہے کوئی کلرک کہلاتا ہے ، کوئی پٹواری کہلاتا ہے ، کوئی تحصیل‌دار کہلاتا ہے ، یہ سب لوگ گنگا جمنا کی طرح ہیں ۔ گنگا جمنا کے کنارے پر کبھی آریاؤں کا راج تھا ۔آریہ راج کرنے آئے ۔ کبھی کوئی راج کرنے آیا ، کوئی مغل آیا تو انہوں نے راج کیا ۔ پٹھان آئے تو انہوں نے بھی یہاں راج کیا لیکن گنگا جمنا نے اپنا پیشہ نہیں چھوڑا اور وہ ہمیشہ کھیتوں کو ہرا کرتی ہی رہی ۔ اگر یہ بھارت ماں ودیشوں کے ہاتھوں میں تھی تو گنگا جمنا نے اپنا اثر نہیں چھوڑا لیکن آج کیا حالت ہے ۔ آج کانگریس الیکشن لڑتی ہے، پارٹی الیکشن لڑتی ہے یا کانگریس کے نمائندے لڑتے ہیں ۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے ۔ کانگریس پارٹی نے الیکشنوں کو لڑنے کے لئے آفیسروں کو پرچارک بنا لیا ہے ۔ ان کو اپنا ملازم بنا رکھا ہے ۔ جہاں پر الیکشن کے لئے ورکر نہیں ہیں ۔ جہاں پر ترنگا جھنڈا دکھائی نہیں دیتا ہے

[شری عبدالغنی]

کا حصہ دار ہے ، کیا اس طرح ہوگا ۔ کوئی کس گوتر سے تعلق رکھتا ہو ، کس دھرم سے تعلق رکھتا ہو ، کس سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہو ، لیکن حالت آپ کی اور میری آج یہ ہے کہ اس سرکار کے راج میں اس طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا کہ یو ۔ پی ۔ کی جو بڑی اسٹیٹ ہے جس کی ۸-۷ کروڑ کی آبادی ہے اگر وہ چل سکتی ہے تو باقی دیش کو چھ حصوں میں کیوں نہیں بانٹا جا سکتا ہے ۔ لیکن وہاں چاہئے یہ کہ ایک ایک جگہ کا ایک ایک چودھری ہو جسے چیف منسٹر کہتے ہیں ۔ اس کی پھر ایک سینا ہو ۔ سینا کے ساتھ دوسری سینا ہو ، اس لئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس اسپرٹ کو بدلنے کے لئے اس بجٹ میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے ۔ ہم لوگوں کی اور بہن بھائیوں کی راہ نمائی کے لئے سرکار اس طرح سے کرے کہ ملک میں ایک جذبہ پیدا ہو سبھی گوتر اور برادری اور علاقے ایک سا بولیں اور چالیں ۔ تو اس سے دیش کہیں بڑا ہو سکتا ہے ۔ اگر یش بڑا ہے تو ہمیں اونچا اٹھنا چاہئے اور ہمیں اپنے دیش کو اس طرح سے تقسیم کرنا چاہئے کہ جہاں نہ صوبائی تعصب بنے جہاں نہ زبانوں کا جھگڑا

کو بنا سکتے ہیں کل ان کو گرا بھی سکتے ہیں - اپنی کوالٹیز پر آپ بنئے اور اپنی پارٹی کی چرچا کیجئے کہ ہم نے یہ کیا - وہ کیا - یہ اڑیسہ میں جو بھوک مری ہے یا کسی اور جگہ ہے اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کانگریس کا دوش نہیں ہے موسم کا دوش ہے ، روپئے کی کمی کا دوش ہے - باہر سے آنے والی گندم کم آئی یا وقت پر نہیں آئی اس کا دوش ہے - میں یہ بات مان سکتا ہوں - میں کانگریس کو ہی نہیں اپنے آپ کو بھی برابر کا ساتھی مانتا ہوں - لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایڈمنسٹریشن جو پوتر ہوگا وہی دنیا میں سب سے زیادہ بہتر سپھلتا حاصل کرسکتا ہے - آپ اس کو ناپاک نہ کیجئے - اسے اپنی پارٹی کے دھندوں میں استعمال نہ کیجئے کیونکہ اس سے دیش بگڑنے والا ہے - اس سے دیش کا کچھ بننے والا نہیں ہے -

اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کیسے کام میں سپھل ہوں مجھے باجپئی جی کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں اشوک مہتا نے یہ کہا اور کیوں اشوک مہتا اس طرح سے مائل ہو رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی مدد سے یہاں پر انڈو-پاک کوئی پراجیکٹ بنانا چاہئے ہیں - میں سمجھتا ہوں کہ آج ساری دنیا وہاں پر کوآپریٹیو کے ڈائریکٹر جاتے ہیں، رجسٹرار جاتے ہیں، ریونیو کے آفیسر جاتے ہیں اور دوسرے تمام محکموں کے لوگ جاتے ہیں اور وہاں جاکر کانگریس کے نمائیندوں کے لئے کنویسنگ کرتے ہیں - اس طرح کا جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ بالکل غلط ہے - اگر وہ لوگ آج کانگریس کا ساتھ دے سکتے ہیں تو کل کو دوسرے دیش دروہیوں کا بھی ساتھ دے سکتے ہیں - کیونکہ میں جہاں جن آفیسروں کے بارے میں کہتا ہوں - ان آفیسروں کے بارے میں دیش کے نیتا مہاتما گاندھی نے یہ کہا تھا کہ ہم ان سے بدلا لینا نہیں چاہتے ہیں - کہ انہوں نے انگریزوں کے اشاروں پر کام کیا تھا لیکن یہ ہمارے بھائیوں کی بھول ہے کہ وہ آفیسر کانگریس کا ٹول بنکر الیکشن میں کام کرتے ہیں - اس الیکشن میں جہاں ڈیموکریسی کا نام لیا جاتا ہے وہ اکثر جاکر ووٹنگ کرتے ہیں - یہ راستہ بالکل غلط ہے وہ آفیسر پھر دیش دروہ کر سکتا ہے - آج اس طرح پارٹیوں کے لئے وہ اپنا کسب چھوڑ کر ، گنگا جمنا کے پوتر کام کو چھوڑ کر ، کانگریس پارٹی کے ٹول بن جاتے ہیں - پھر بھی اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے - تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سرکار بالکل بھول میں ہے - وہ لوگ جو ان

پولیس اسٹبلشمنٹ کے سپرانٹنڈنٹ نے پارلیمنٹ اسٹریٹ کے مجسٹریٹ کے سامنے ایک ایف - آئی - آر درج کیا اور اس میں کہا گیا کہ ایک بنک میں فراڈ ہوا اور ایک بنک میں بےایمانی ہوئی - اس میں تمام دنیا بھر کی دفعات لگا دی گئیں - اس طرح کے لوگ وہاں پر موجود ہیں لیکن سرکار اس کا ذکر نہیں کرتی ہے - باوجود اس کے کہ اس طرح کی بد دیانتی ہوتی ہے اور ریزرو بنک بھی اس کنائیوینس میں شامل ہو جاتا ہے - میں کہتا ہوں کہ ایک بنک میں ۴۶ لاکھ روپیہ بلیک کا پڑا ہوا ہے - ٹی - ٹی - کرشنماچاری چلے گئے ہیں - لوک سبھا میں چلے گئے ہیں - یہاں فائننس منسٹر تھے - لیکن وہ یہاں کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یہ باتیں جو ہیں یہ تمام غلط ہیں - اگر ایک خاندان مان کر ساری دنیا کو امریکہ یا رشیا ہندوستان کی مدد کے لئے آتا ہے، میں کہتا ہوں کہ آنا چاہئے - اگر نہیں آتا ہے تو وہ اس دنیا کا اگوا کہلانے کے قابل نہیں ہے - کیوں کہ ہندوستان اس وقت دنیا کی تہذیب میں ، دنیا کی شرافت میں، روحانیت میں، سب سے بڑا علم براد ہے - چین کا اگر کوئی جواب ہے تو وہ ہندوستان ہی ہے - ہندوستان میں اگر حالت خراب ہو جائے ، بھوکمری بڑھ جائے ، غریبی بڑھ جائے ، آفیسرس کیا ، فارمرس

[شری عبدالغنی]

ایک گھروندا بنکر رہ گئی ہے ، ایک چھوٹا سا کٹمب بن کر رہ گئی ہے - کیا باجپئی یا عبدالغنی کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے - ہوتا ہے- لیکن اس کے معنی کیا یہ ہوتے ہیں ؟ آج دنیا کو بنانے کے لئے اگر امریکہ اس طرح سے اپنی سروسیز پیش کرتا ہے جیسے رشیا پیش کرتا ہے تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہئے، اس کا سواگت کرنا چاہئےاور کہنا چاہیے کہ امریکہ سرکار اس وقت اپنی بگڑی ہوئی حالت کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے - یہ کون نہیں جانتا کہ ہمارے روپئے کی طاقت کتنی رہ گئی - سترہ پیسہ یا تیرہ پیسہ رہ گئی ہے - آج ایک بڑے سے بڑا آفیسر جو ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم اچھی طرح سے نہیں دے سکتا ہے - ان کی صحت کی دیکھ بھال اچھی طرح سے نہیں کر سکتا ہے - کیوں کہ آج مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے - کوئی افسر اگر رشوت لیتا ہے تو ہم اس کو چور کہتے ہیں لیکن سرکار نے قسم کھا لی ہے کہ غلط راستہ پر ڈال دیا جائے - میں نے بینکنگ کے بارے میں یہاں پر کئی بار قصہ اٹھایا - بنک جو بھی ہو، چاہے ریزرو بنک ہو ، یا دوسرا بنک ہو ، لیکن وہ ملک کی باڑ ہیں - جہاں تک اکانامک حالت کا تعلق ہے لیکن ان میں بددیانتی ہوئی - جولائی ۶۵ میں سرکار کی طرف سے

وہ اپنا راستہ ہی بھول جائے ۔ کیوں کہ یہ سرکار کو ماننا چاہئے کہ تیسری یوجنا کے باوجود ہم آج کھیتی‌باڑی میں ترقی نہیں کر سکے ہیں ۔ یہ سرکار کو ماننا چاہئے کہ تیسری یوجنا کے باوجود آج انڈسٹریز میں ہم اتنی ترقی نہیں کر سکے ہیں جتنی کہ ہم توقع کرتے تھے ۔ یہ سرکار کو ماننا چاہئے کہ ایجوکیشن میں جو ہم توقع کرتے تھے کہ ہم ان یوجناؤں میں ایک ایک گھر میں تعلیم پھیلا دیں گے وہ ہم نہیں پھیلا سکے ۔ ہم ڈاکٹر نہیں پیدا کر سکے ۔ ہم ہسپتال نہیں بنا سکے اور اگر ہسپتال بنا سکے تو وہاں دوائیاں نہیں پہنچا سکے ۔ ہم فرٹلائزر کے کارخانے لگا سکے لیکن فرٹلائزر ہم کسان تک نہیں پہنچا سکے ۔ اگر بارش نہیں ہوئی تو ہم نے خدا کو گالیاں دینی شروع کر دیں کہ بھگوان نے تباہ و برباد کر دیا لیکن اس کا کوئی بدل نہیں پیدا کر سکے ۔ ہم ٹیوب ویل ، پمپنگ سیٹس اور چھوٹے کنوئیں اس طرح سے نہیں لگا سکے کہ اگر کوئی بپتا آئے تو اس کا ہم مقابلہ کر سکیں ۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ پانی کی کمی ہونے سے ہمارے پاورہاؤسیز جو تھے وہ اتنے دھیمے پڑ گئے کہ ہم نے لوگوں سے کہا کہ ہم تمہیں ۲۰ فی صدی بجلی بھی نہیں دے سکتے ۔ سرکار ہوتی ہے اس بات کے لئے کہ وہ ایسے موقعہ پر مردوں کی طرح کھڑی ہو جائے ۔ کیا ، دوسرے کیا ، سب کے سب اپنی جگہ سے نیچے چلے آئیں ۔ تو امریکہ کا کچھ بننے والا نہیں سوائے اس کے کہ وہ بھی ختم ہو جائے گا ۔ تو اگر امریکہ آتا ہے ۔ تو آئے ۔ باجپئی جی یہ کہتے ہیں کہ امریکہ آئے ، ایسے ٹرمس میں آئے ، کہ ہمارے دیش کی شان کو ، ہمارے دیش کی آزادی کو ، ہمارے دیش کی اونچائی کو ، کوئی دھکا نہ لگے تو میں مان سکتا ہوں اور میں قبول کرتا ہوں ۔ روس والوں نے جنگ کے دوران ہماری .و مدد کی ہے اس کے لئے میں ان کا شکرگذار ہوں ۔ اگر رشیا ہمارے لئے کوئی نیک قدم اٹھانا چاہتا ہے ۔ تو کیوں کہ میں ان کے خیال سے متفق نہیں ہوں اس لئے میں ان کی مدد کو کہوں کہ انہوں نے مدد غلط کی ہے یا امریکہ والوں کو کہوں کہ وہ غلط ہیں، تو مناسب نہیں ہوگا ۔ باقی رہا کہ یہ جو آفیشیل پارٹی کے بڑے بڑے سنیر آفیسرس موجود ہیں ان کے لئے میں یہ کہنا نہیں چاہتا ۔ لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ہاؤس میں میں نے سب رنگ دیکھے ہیں کہ اگر آج امریکہ کو دبانا ہے تو چاروں طرف سے ہاؤس میں گالیاں پڑنی شروع ہو گئیں ۔ اگر روس کو اٹھانا ہے تو روس کی مہما شروع ہو جاتی ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ سرکاریں ایسا کرتی ہیں ۔ لیکن سرکار ایسا نہ کرے کہ

ہوں کہ بینکنگ میں بڑھتی ہوئی بے ایمانیوں ، لوٹ کھسوٹ اور جو نیپوٹزم اور فیورٹزم چلتا ہے اور ایل - آئی - سی جس کا کروڑوں روپیہ غلط طور پر لگا ہے اور جس میں بہت ہی ترٹیاں آ گئی ہیں ان کے خلاف سرکار ایک کمیشن مقرر کرے تاکہ بینکنگ اور ایل - آئی - سی کی جو غلط باتیں ہیں ان کو کسی طرح سے چیک کیا جائے -

دوسری گذارش یہ ہے کہ سارے دیش میں کھانے پینے کی چیزوں کا ایک دام مقرر ہو تاکہ ملک میں کھانے پینے کی وجہہ سے کوئی افرا تفری نہ ہو - گورنمنٹ ایک کمیشن بٹھائے جو یہ وچار کرے کہ کنیا کماری سے لے کر شری نگر کے آخری حصہ تک اور ادھر آسام سے لے کر گجرات کے آخری حصہ تک ایک ہی قیمت مقرر ہو - اس کو کسی طرح سے مقرر کیا جائے - اور کسی طرح سے گورنمنٹ اس کے لئے سبسیڈی دے اس کے بارے میں کمیشن وچار کرے -

تیسرا یہ کہ جس منسٹری کے زیر سایہ کروڑوں روپیئے کے پرمٹ ہر روز بمبئی میں بک جاتے ہیں - جس نے کروڑوں روپیئے کے امپورٹ لائسنس بغیر بنک کلیرنگ سارٹیفیکٹ جاری کرائے جس کے تحت ایک کارخانہ اور دوسرے کارخانہ میں ایک فیکٹری اور دوسری فیکٹری میں اس طرح کا برتاؤ

[شری عبدالغنی]

اگر قدرت کی طرف سے بارش ہو جاتی ہے تو اس میں سرکار کا کیا زور ہے یا اپوزیشن والوں کا کیا زور ہے - وہ تو بھگوان کی بارش ہوتی ہے اور اس سے کسان کی کھیتی باڑی ہری ہو جاتی ہے لیکن اگر بارش نہ ہو پھر بھی ہم کچھ کر پاتے ہیں تب سرکار اچھی کہلاتی ہے اور تب سرکار کے لئے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سرکار اچھی ہے اور یہ اصل میں جنتا کی مدد کرتی ہے - *{Time bell rlmsj}* تو میں ختم کر دوں ؟

उपसभापति : आप 15 मिनट बोल चुके हैं ।

شری عبدالغنی : اس سیشن میں تو شاید میری ایک ہی تقریر ہوگی - ابھی تو میں ایک ہی پہلو پر بولا ہوں اور میں تھوڑا آگے چلنا چاہتا ہوں - اگر آپ اجازت دینگی - اور اگر اجازت نہیں دینگی تو بیٹھ جاؤں گا -

उपसभापति : वक्त बहुत कम है ।

We have to finish the Bill today. You may take anothor 5 to 7 minutes after the lunch hours.

The Hous stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned at thirty one minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of THE clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA) in the Chair.

شری عبدالغنی : وائس چیر مین مہودے - میں اس سے پیشتر کہ اپنی گذارشات کو ختم کروں - میں آپ کے دوارا اپنی سرکار سے یہ مطالبہ کرتا

انسیڈینٹ کو جتنا بھی ہو سکے سختی سے دبایا جائے ۔

کشمیر کی سمسیا کو ہمیشہ کے لئے حل کرنے کے لئے شیخ عبداللہ کو رہا کیا جائے اور شیخ عبداللہ کی مدد سے اس مسئلہ کا ہمیشہ کے لئے سلجھاؤ کیا جائے ۔

میری یہ بھی درخواست ہے کہ ایمرجنسی کو ختم کیا جائے ۔ ایمرجنسی کی آج ضرورت نہیں ۔ سب کے سب مل کر اندرا جی کے ہاتھ مضبوط کریں ۔ اگر کوئی بالکل دیش دروھی ہے جس سے یہ خطرہ ہے کہ وہ دیش کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس پر کھلے بندوں مقدمہ چلا کر جیل میں رکھا جائے اور جو سخت سے سخت سزا سرکار دینا چاھتی ہے دے ۔

دیش کی مضبوطی کے لئے پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو فوج کی طرح دیش کے بچاؤ کی دوسری لائن بنایا جائے اور پولیس کو سینٹرل سبجکٹ رکھا جائے تاکہ سارے دیش میں مضبوطی آ سکے ۔

ایک عرض یہ ہے کہ جیسے یہ حقیقت ہے کہ کشمیر بھارت کا ہے ، جیسے یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں آتما اور پرماتما کا گیان دینے میں بھارت سب سے اونچا ہے ، اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان میں جو چھ کروڑ مسلمان بستے ہیں وہ ہندوستان کا ایک انگ کیا گیا ہے جس میں بڑا مت بھید ہونے کی وجہہ سے ایک اگر کروڑ پتی بنگیا تو دوسرا برباد ہوا ۔ جس منسٹری کے تحت ایسی چیزوں کے امپورٹ ہوئے جیسے ریان کا جس کے پردہ میں پولور ، نئے نئے کوٹ اور پتلونیں آئی ہیں اس کے ٹکڑے آئے اور وہ بکے ۔ اور جس منسٹری نے پبلک انٹرسٹ کے تحت ڈیوٹی بھی ہٹا دی اس منسٹری سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ ریزائن کرے ۔ وہ کامرس منسٹری ہے ۔ ایک منسٹر جو فارن کے ، دوسرے ممالک کے ، منسٹر ہیں ، پہلے کامرس کے تھے ، پھر کھانے پینے میں آئے ، وہاں سے فارن منسٹر بنے ، ان کے وقت میں کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا باہر لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ جب پاکستان سے ہماری لڑائی ہوئی کوئی بھی ہمارا مدد گار نہیں تھا ، کسی دیش میں ہمارے لئے ہمدردی کے نعرے نہیں اٹھے تھے ۔ اس کو اس نالائقی کی وجہہ سے ریزائن کرایا جائے ۔

ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں ۔ آنے والے الیکشن میں ڈیموکریسی کو زندہ رکھنے کے لئے سرکار اس بات کا بالکل نیشچے کرے کہ وہ کسی طرح سے بھی افسروں کو الیکشن میں سپریم نہیں بنائے گی ۔ اگر بنائے گی تو اس سے پریشانی بڑھے گی ۔

آج ملک میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں جیسا ابھی بستر میں ہوا ۔ ایسے

خاص طور پر سمجھ لیں کہ کوئی چاہے وہ کتنی ہی اونچی پدوی پر کیوں نہ ہو اگر ایبوز آف پاور کی وجہہ سے یا کرپشن کی وجہہ سے یا نالائقی کے وجہہ سے الگ کیا جاتا ہے تو پھر اس کو بالکل اسی طرح سے بلیک لسٹ کیا جائے جیسا کہ بیوپاری کو بلیک لسٹ کر دیتے ہیں یا کسی بد معاش کو بلیک لسٹ کر دیتے ہیں جو سبھا اور سوسائٹی کے لائق نہ ہو اسی طرح سے ان کو بھی پالیٹیکس میں ریڈ لائن کر دی جائے اور جس طرح سے بیرین مترا اور دوسرے لوگوں کو پھر موقعہ دیتے ہیں ان کو موقعہ نہ دیا جائے ۔

آخری عرض کرتا ہوں کہ اتنی بڑی بات ہوئی پنجاب میں ۔ کیا کچھ ہوا ؟ ہند سرکار کے ایک منسٹر کو ڈسمس کیا جاتا ہے ۔ کیوں ڈسمس کراتے ہیں ، اس کا سرکار ہی جواب دے سکتی ہے ۔ پھر اسی کو موقعہ دیا جاتا ہے کہ وہ الیکشن لڑے ۔ اس کو کانگریس کا ٹکٹ ملے ، مجھے اس سے بحث نہیں ۔ میری عرض یہ ہے کہ سرکار اس وشے میں چاہے جتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو ۔ اس کے اوپر وہ ایکشن لے ۔ اس کی بد دیانتی ، کمزوری یا ایبوز آف پاور کی وجہہ سے اس کو پھر سے کسی طرح سے بھی پالیٹکس میں آنے نہ دے ۔ جیسے کہ ایوب نے بٹھا دیا تھا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے غداری کی تھی عوام کے

[شری عبدالغنی]

ہیں ۔ ان کے ساتھ اب ایسا سلوک ہو جس سے ان کے من کا یہ احساس کہ وہ ہندوستان میں برابری پر نہیں ہیں ختم ہو جائے ۔ میں ایک مثال نہیں کئی مثالیں دے سکتا ہوں ۔ بنارس یونیورسٹی میں گڑ بڑ ہوئی ، علی گڑھ میں بھی ہوئی ۔ کچھ لڑکوں نے کی ۔ میں نے کنڈم کیا ۔ لیکن دونوں میں مت بھید ہو ۔ ایک یونیورسٹی میں ایک طرح کا برتاؤ ہو ، دوسری یونیورسٹی میں دوسری طرح کا برتاؤ ہو ، تو یہ دیش کو اونچا نہیں لے جائیگا ، نیچے لے جائیگا ۔

ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں ۔ جب ملک میں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت ایک ہو جائے پھر دیکھا جائے کہ چاہے ایک چپراسی ہو ، کلرک ہو ، آفیسر ہو ، اس کے لئے اپنا پیٹ بھرنے میں دقت نہ ہو ۔ ابھی تک ہم ہیلتھ کا انتظام ملک میں ایسا نہیں کر سکے کہ ہیلتھ سروسیز فری دے سکیں ۔ جب تک یہ نہیں ہو جاتا ان کی تنخواہوں کی اسکیل اس طرح سے رکھے جائے جس سے آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنا سکیں ۔

میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اندرا جی اور اندرا جی کے ساتھی جن پر دیش کے چلانے کا بوجھا ہے اس بات کو

ساتھ ۔ اسی طرح سے ان لوگوں کو ٹھنڈا کر دیا جائے تاکہ اندرا جی کا راستہ صاف ہو اور وہ صفائی کے ساتھ اپنے دیش کو آگے لے جا سکیں ۔

†[**श्री अब्दुल गनी** (पंजाब) : चेयरमेन साहब, एप्रोप्रिएशन बिल का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि सरकार अपनी जरूरियात को हाउस के सामने लाई है। मैं श्री राज नारायण सिंह जी के साथ मुत्तफिक नहीं हूं कि इस सरकार को इसकी त्रुटियों के कारण कोई पैसा नहीं देना चाहिए, इसका कोई बिल पास नहीं करना चाहिए।

[THE DEPUTY CHAIRMAN IN THE CHAIR]

लेकिन जहां मैं इसका स्वागत करता हूं वहां कुछ गुजारिशात डिप्टी चेयरमेन के जरिए सरकार के सामने रखना चाहता हूं। सरकार दावा करती है कि वह मरहूम पंडित जवाहर लाल नेहरू के नकशे कदम पर चल रही है लेकिन इसका अमल इसके ख़िलाफ है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस मशहूर हुब्बे वतन को—जिसे शेरे हिन्द भी कहा गया शेरे काश्मीर भी कहा गया—शेख अब्दुला को इतनी इज्जित बख्शी थी, रिहा करके कि वह चाहते थे कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के दरमियान यह काश्मीर की प्राब्लेम जो है जो आए दिन तल्ख़ होता जाता है उसको किसी तरह से हल किया जाए। इख्तलाफ राय हो सकता है। कल डाह्याभाई पटेल ताकत में आ सकते हैं और मेरी बहन इन्दिरा जी अपोज़िशन में जा सकती हैं लेकिन इसके मायने यह कहां है कि अगर जवाहर लाल नेहरू ने कोई बात की थी और उठाई थी कि किसी तरह पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के दरमियान जो एक ही झगड़ा है और वह काश्मीर का है उसे सोल्व किया जाए उसका जवाब यह दिया जाए कि सरकार शेख अब्दुला को जेल में रखे, नज़र बन्दी की हालत में रखे और इससे यह मदद न ले कि काश्मीर का मसला हल हो। कौन नहीं जानता कि काश्मीर की वजह से ही अभी-अभी जो आख़री जंग हुई और जिसमें हमारे हिन्दुस्तानी विजयी हुए पाकिस्तान के साथ उसका कारण काश्मीर था। या तो सरकार आए दिन यह न कहे कि वह पंडित जवाहर लाल नेहरू के कदमों पर चलना चाहती है और अगर कहती है कि चलना चाहती है तो उसे शेख अब्दुला को रिहा करना चाहिए और शेख अब्दुला के जरिए कश्मीर के मसले को पाकिस्तान के साथ हमेशा के लिए निबटाना चाहिए। उसको निबटाने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान अपनी ज़िद से बाज़ आए। वह जानता है कि काश्मीर हिन्दुस्तान का है, उसने उसके एक हिस्से पर कब्ज़ा कर रखा है। मुझे हैरत हुई थी डिप्टी चेयरमेन साहब आपको याद होगा कि जब यहां से श्री लाल बहादुर शास्त्री चले थे तो सबने अपनी दुआएं दी थीं और मैंने दुवा देते हुए यह कहा था कि अगर जनरल अयूब यह कहें कि मैं कश्मीर के मुतल्लिक बात नहीं करूंगा तो मैं समझ सकता हूं क्यों कि उन्होंने उसपर कब्ज़ा कर रखा है लेकिन हम कहें कि हम काश्मीर के मुतल्लिक कोई बात नहीं करेंगे तो इसे मैं नहीं समझ सकता। आज भी इस मसले का हल, ताकि मुल्क पर जो करोड़हा अरबहा रुपए का बोझ पाकिस्तान की लड़ाई में पड़ा और हमारे जो तरक्की के तहमीरी काम हैं वह रुके, उसका कोई न कोई उपाय हो।

मैं इसके साथ यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस वक्त एमरजेंसी के पर्दे में अपने बेशुमार बहनों भाइयों को जेल में रखा है। कोई डेमोक्रेसी की अलम बरदार सरकार गैर मुतमैयन वक्त के लिए बगैर मुकदमा चलाए उन लोगों को जेल में रखे जिन्होंने कि उनसे ज्यादा अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए कैद काटी है ठीक नहीं है। इन गद्दियों पर बैठने वाले कई ऐसे हैं जिन्होंने गांधी जी की

t[ ] English translation.

[श्री अब्दुल गनी]

शकल नहीं देखी, कई ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेज के राज में कांग्रेस का नाम नहीं लिया और कई ऐसे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन यह सब मुहिब्बे-वतन बन कर, क्योंकि ताकत उनके हाथ में है, ऐसा कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि अगर कोई देश द्रोही हो तो उसपर मुकदमा चलाओ न कि यह कि इस पर्दे में केरल के तमाम लोगों को डेमोक्रेसी से महरूम कर दो। यह सरकार जो डेमोक्रेसी की अलम बरदार है अपने हाथ में ऐसा डंडा रखना चाहती है जिससे डेमोक्रेसी का गला घोंटा जाए तो मैं समझता हूं कि यह पंडित जवाहर लाल नेहरू के नक्शे कदम पर नहीं चलती। मैं इस बात पर भी हैरान होता हूं कि आखिर डेमोक्रेसी के मायने क्या यह हैं कि अगर शंकर जी कामयाब हो जाएं तब तो केरल में डेमोक्रेसी चलेगी और अपोजिशन वाले जीत जाएं तो केरल में डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। यह बातें जो हैं किसी सरकार को सजती नहीं हैं। इससे सरकार की ताकत बनती नहीं है। जहां मैंने यह कहा वहां यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो नागालैंड का किस्सा हुआ, यह जो मीज़ो का किस्सा हुआ यह आए दिन महाराष्ट्र और मैसूर की जंग हो और आंध्रा और तमिल की जंग हो . . .

श्री अकबर अली खांन (आंध्र प्रदेश) : आंध्रा और तमिल में कोई जंग नहीं है।

श्री अब्दुल गनी : मेरे भाई अकबर अली यह कह रहे हैं लेकिन एक मराठी भी यह कबूल नहीं करता कि वह तमिल के नीचे चला जाए या एक तमिल यह कबूल नहीं करता कि वह आंध्रा या महाराष्ट्र के नीचे चला जाए। तो मैं यह कह रहा था कि यह जो छोटे-छोटे फर्क आप पैदा कर रहे हैं। मैं बचपन में पढ़ा करता था महाराजा अली राज चकरवर्ती महाराज 6 गांव के राजा हुआ करते थे। तो आज चप्पे-चप्पे पर नई-नई स्टेट बनाई जा रही हैं और बनती जा रही हैं। यह जो टेंडेंसी है वह देश को कहां लिए जा रही है। आप अरबहा रुपया मंजूर कराएं मुझे कोई दुःख नहीं है क्योंकि कोई सरकार बिना रुपये के नहीं चल सकती। मैंने अपनी जिन्दगी में बजट की मुखालफत नहीं की। इसलिए नहीं की कि कोई भी सरकार जो अपोजिशन की हो या मौजूदा कांग्रेस की हो वगैर इसके नहीं चल सकती लेकिन हमारी टेंडेंसी किस तरफ चल रही है कि यह जो छोटे-छोटे घरौंदे आप बनाने जा रहे हैं और उसको आप लैंगविज का बहाना देते हैं? मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों आज सरकार इस बात की तरफ विचार नहीं करती कि अपने देश की हालत को सुधारने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन, जिसे आप कहते हैं कि हिन्दुस्तान एक है, हर हिन्दुस्तानी बराबर का हिस्सेदार है, क्या इस तरह होगा। वह किसी गोत्र से ताल्लुक रखता हो किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो किसी सोसाइटी से ताल्लुक रखता हो लेकिन हालत आपकी और मेरी आज यह है इस सरकार के राज में। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता कि यू० पी० की जो बड़ी स्टेट है जिसकी 7-8 करोड़ की आबादी है अगर वह चल सकती है तो बाकी देश को 6 हिस्सों में क्यों नहीं बांटा जा सकता है। लेकिन वहां चाहिए यह कि एक-एक जगह का एक-एक चौधरी हो जिसे चीफ मिनिस्टर कहते हैं। उसकी फिर एक सेना हो। सेना के साथ दूसरी सेना हो इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस स्पिरिट को बदलने के लिए इस बजट में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। हम लोगों की और बहन भाइयों की रहनुमाई के लिए सरकार इस तरह से करे कि मुल्क में एक जज़बा पैदा हो, सभी गोत्र और बिरादरी और इलाके एक सा बोलें और चलें तो इससे देश कहीं बड़ा हो सकता है। अगर-देश बड़ा है तो हमें ऊंचा उठना चाहिए और हमें अपने देश को इस तरह से तकसीम करना चाहिए कि जहां न सूबाई तअस्सुब बने न जबानों का झगड़ा हो और हम मिलजुल कर अपने देश की दूसरी योजनाओं को कामयाब बनाने की कोशिश करें।

मुझे एक बात कहनी है और वह यह है कि बदकिस्मती से इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो गंगा और जमना की तरह पवित्र होता है जिसमें छोटे-बड़े मुलाजम सब होते हैं इसमें कोई आफिसर कहलाता है कोई क्लर्क कहलाता है कोई पटवारी कहलाता है कोई तहसीलदार कहलाता है यह सब लोग गंगा जमना की तरह हैं। गंगा जमना के किनारे पर कभी आर्यों का राज था। आर्य राज करने आए, कभी कोई राज करने आया, कोई मुगल आया तो उन्होंने राज किया, पठान आए तो उन्होंने भी यहां राज किया लेकिन गंगा जमना ने अपना पेशा नहीं छोड़ा और वह हमेशा खेतों को हरा करती ही रही। अगर यह भारत मां विदेशियों के हाथों में थी तो गंगा जमना ने अपना असर नहीं छोड़ा लेकिन आज क्या हालत है? आज कांग्रेस इलेक्शन लड़ती है पार्टी इलेक्शन लड़ती है या कांग्रेस के नुमाइन्दे लड़ते हैं। यह कहना बिल्कुल गलत है कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शनों को लड़ने के लिए आफिसरों को प्रचारक बना लिया है। उनको अपना मुलाजम बना रखा है। जहां पर इलेक्शन के लिए वरकर्स नहीं हैं जहां पर तिरंगा झंडा दिखाई नहीं देता है वहां पर को-आपरेटिव के डायरेक्टर जाते हैं रजिस्ट्रार जाते हैं, रेवेन्यू के आफिसर जाते हैं और दूसरे तमाम महकमों के लोग जाते हैं और वहां जाकर कांग्रेस के नुमाइन्दों के लिए कनवासिंग करते हैं। इस तरह का जो रास्ता आपने अख्तियार किया है वह बिल्कुल गलत है। अगर वह लोग आज कांग्रेस का साथ दे सकते हैं तो कल को दूसरे देश द्रोहियों का भी साथ दे सकते हैं। क्योंकि मैं जहां जिन आफिसरों के बारे में कहता हूं उन आफिसरों के बारे में देश के नेता महात्मा गांधी ने यह कहा था कि हम उनसे बदला लेना नहीं चाहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के इशारों पर काम किया था लेकिन यह हमारे भाइयों की भूल है कि आफिसर कांग्रेस का टूल बनकर इलेक्शन में काम करते हैं। इस इलेक्शन में जहां डेमोक्रेसी का नाम लिया जाता है वह अकसर जाकर वोटिंग करते हैं। यह रास्ता बिल्कुल गलत है वह आफिसर फिर देश द्रोह कर सकता है। आज इस तरह पार्टियों के लिए वह अपना कसब छोड़ कर गंगा जमना के पवित्र काम को छोड़ कर कांग्रेस पार्टी के टूल बन जाते हैं। फिर भी अगर यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी है तो मैं यह कहता हूं कि यह सरकार बिल्कुल भूल में है। वे लोग जो उनको बना सकते हैं कल उनको गिरा भी सकते हैं। अपनी क्वालिटीज पर आप बनिए और अपनी पार्टी की चर्चा कीजिए कि हमने यह किया वह किया। यह उड़ीसा में जो भूखमरी है या किसी और जगह है उसके बारे में आप कह सकते हैं कि इसमें कांग्रेस को दोष नहीं है, मौसम का दोष है, रुपये की कमी का दोष है। बाहर से आने वाली गन्दुम कम आई या वक्त पर नहीं आई इसका दोष है मैं यह बात मान सकता हूं। मैं कांग्रेस को ही नहीं अपने आपको भी बराबर का साथी मानता हूं। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो पवित्र होगा वही दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर सफलता हासिल कर सकता है। आप इसको नापाक न कीजिए, इसे अपनी पार्टी के धन्धों में इस्तेमाल न कीजिए क्योंकि इससे देश बिगड़ने वाला है, इससे देश का कुछ बनने वाला नहीं है।

अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज हम कैसे काम में सफल हों मुझे वाजपेयी जी की इस बात से बिल्कुल इत्तफाक नहीं है जो वह यह कहते कि क्यों अशोक महता ने यह कहा और क्यों अशोक महता इस तरह से मायल हो रहे हैं कि वह अमेरिका की मदद से यहां पर इंडोपाक, कोई प्राजेक्ट बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आज सारी दुनिया एक घरोन्दा बनकर रह गई है, एक छोटा सा कुटुम्ब बन कर रह गई है। क्या वाजपेयी या अब्दुल गनी के घर में झगड़ा नहीं होता है? होता है लेकिन इसके मायने क्या यह होते हैं? आज दुनिया को बनाने के लिए अगर अमरीका इस तरह से अपन

[श्री अब्दुल ग़नी]

सर्विसिज़ पेश करता है जैसे रशिया पेश करता है तो हमें उसको कबूल करना चाहिए उसका स्वागत करना चाहिए और कहना चाहिए कि अमेरिका सरकार इस वक्त अपनी बिगड़ी हुई हालत को ठीक करना चाहती है। यह कौन नहीं जानता कि हमारे रुपये की ताकत कितनी रह गई। सतरह पैसे या तेरह पैसे रह गई है। आज एक बड़े से बड़ा आफिसर जो है उसकी हालत यह है कि वह अपने बच्चों को तालीम अच्छी तरह से नहीं दे सकता है, उनकी सेहत की देख भाल अच्छी तरह से नहीं कर सकता है क्योंकि आज महंगाई इतनी बढ़ गई है। कोई आफिसर अगर रिश्वत लेता है तो हम उसको चोर कहते हैं लेकिन सरकार ने कसम खा ली है कि गलत रास्ते पर डाल दिया जाए। मैंने बैंकिंग के बारे में यहां पर कई बार किस्सा उठाया। बैंक जो भी हो चाहे रिज़र्व बैंक हो या दूसरा बैंक हो लेकिन वह मुल्क की बाड़ हैं जहां तक इकोनोमिक हालत का ताल्लुक है लेकिन इनमें बद-दयान्ती हुई। जुलाई 1965, में सरकार की तरफ से पोलिस स्टेब्लिशमेंट के सुपरिंटेंडेंट ने पार्लियामेंट स्ट्रीट के मजिस्ट्रेट के सामने एक एफ० आई० आर० दर्ज किया और उसमें कहा गया कि एक बैंक में फ्राड हुआ और एक बैंक में बेईमानी हुई। उसमें तमाम दुनिया भर की दफात लगा दी गई। इस तरह के लोग वहां पर मौजूद हैं लेकिन सरकार उसका ज़िकर नहीं करती है। बावजूद इसके कि इस तरह की बद-दयान्ती होती है और रिज़र्व बैंक भी कन्नाइवेंस में शामिल हो जाता है। मैं कहता हूं कि एक बैंक में 46 लाख रुपये ब्लैक का पड़ा हुआ है। टी० टी० कृष्णमाचारी चले गये हैं। लोक सभा में चले गये हैं। यहां फाइनांस मिनिस्टर थे। लेकिन वह यहां कहते हैं कि कोई बात नहीं यह बातें जो हैं यह तमाम गलत हैं। अगर एक खानदान मान कर सारी दुनिया को अमेरिका या रशिया हिन्दुस्तान की मदद के लिए आता है मैं कहता हूं कि आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वह इस दुनिया का अगवा कहलाने के काबिल नहीं है। क्योंकि हिन्दुस्तान इस वक्त दुनिया की तहज़ीब में, दुनिया की शराफत में, रूहानियत में सबसे बड़ा अलमबरदार है। चीन का अगर कोई जबाब है तो वह हिन्दुस्तान ही है। हिन्दुस्तान में अगर हालत खराब हो जाए भूखमारी बढ़ जाए, गरीबी बढ़ जाए आफिसर्स क्या, फारमर्स क्या, दूसरे क्या, सबके सब अपनी जगह से नीचे चले जाएं तो अमेरिका का कुछ बनने वाला नहीं सिवाए इसके कि वह भी खत्म हो जाएगा । तो अगर अमेरिका आता है तो आए। वाजपेयी जी यह कहते हैं कि अमेरिका आए ऐसे टर्म्स में आए कि हमारे देश की शान को हमारे देश की आज़ादी को हमारे देश की ऊंचाई को कोई धक्का न लगे उसे मैं मान सकता हूं और मैं कबूल करता हूं। रूस वालों ने जंग के दौरान हमारी जो मदद की है उसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूं। अगर रशिया हमारे लिए कोई नेक कदम उठाना चाहता है तो क्योंकि मैं उनके ख्याल से मुत्तफिक नहीं हूं इसलिए मैं उनकी मदद को कहूं कि उन्होंने मदद गलत की है या अमेरिका वालों को कहूं कि वह गलत हैं, तो मुनासिब नहीं होगा। बाकी रहा कि यह जो आफिशियिल पार्टी के बड़े बड़े सीनियर आफिसर्स मौजूद हैं उनके लिए मैं यह कहना नहीं चाहता। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि इस हाउस में मैंने सब रंग देखे हैं कि अगर आज अमेरिका को दबाना है तो चारों तरफ से हाउस में गालियां पड़नी शुरू हो गई। अगर रूस को उठाना है तो रूस की महिमा शुरू हो जाती है लेकिन मैं जानता हूं कि सरकारें ऐसा करती हैं। लेकिन सरकार ऐसा न करे कि वह अपना रास्ता ही भूल जाए। क्योंकि यह सरकार को मानना चाहिए कि तीसरी योजना के बावजूद हम आज खेती बाड़ी में तरक्की नहीं कर सके हैं। यह सरकार को मानना चाहिए कि तीसरी योजना के बावजूद आज इण्डस्ट्रीज़ में हम इतनी तरक्की नहीं कर सके हैं जितनी कि हम तवक्को करते थे। यह सरकार को

मानना चाहिए कि एजूकेशन में जो हम तवक्को करते थे कि हम इन योजनाओं में एक एक घर में तालीम फैला देंगे वह हम नहीं फैला सके। हम डाक्टर नहीं पैदा कर सके। हम हस्पताल नहीं बना सके और अगर हस्पताल बना सके तो वहां दवाईयां नहीं पहुंचा सके। हम फरटिलाइज़र के कारखाने लगा सके लेकिन फरटिलाइज़र हम किसान तक नहीं पहुंचा सके। अगर बारिश नहीं हुई तो हमने खुदा को गालियां देनी शुरू कर दीं कि भगवान ने तबाह व बरबाद कर दिया लेकिन उसका कोई बदल नहीं पैदा कर सके। हम ट्यूब वेल पम्पिंग सेटस् और छोटे कुवें इस तरह से नहीं लगा सके कि अगर कोई विपता आए तो उसका हम मुकाबला कर सकें। आज हमारी यह हालत है कि पानी की कमी होने से हमारे पावर हाउसेज जो थे वह इतने धीमे पड़ गये कि हमने लोगों से कहा कि हम तुम्हें 25 फीसदी बिजली भी नहीं दे सकते। सरकार होती है इस बात के लिए कि वह ऐसे मौके पर मर्दों की तरह खड़ी हो जाए। अगर कुदरत की तरफ से बारिश हो जाती है तो उसमें सरकार का क्या जोर है या अपोज़िशन वालों का क्या जोर है? वह तो भगवान की बारिश होती है और उससे किसान की खेती बाड़ी हरी हो जाती है लेकिन अगर बारिश न हो फिर भी हम कुछ कर पाते हैं तब सरकार अच्छी कहलाती है और तब सरकार के लिए यह जजबा पैदा होता है कि यह सरकार अच्छी है और यह असल में जनता की मदद करती है।

(Time bell rings.)

तो मैं खत्म कर दूं?

उपसभापति : आप 15 मिनट बोल चुके हैं।

श्री अब्दुल गनी : इस सेशन में तो शायद मेरी एक ही तकरीर होगी। अभी तो मैं एक ही पहलू पर बोला हूं और मैं थोड़ा आगे चलना चाहता हूं अगर आप इजाजत देंगी और अगर इजाजत नहीं देंगी तो बैठ जाऊंगा।

उपसभापति : वक्त बहुत कम है।

We have to finish the Bill today. You may take another 5 to 7 minutes after the lunch hours.

The House stands adjourned till 2. 30 p.m.

The House then adjourned at thirty one minutes past .one of the clock.

The House reassembled after lunch at ; half past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA) in the chair.

श्री अब्दुल गनी : वाइस चेयरमैन महोदय, इससे पेशतर कि अपनी गुजारीशात को खत्म करूं मैं आपके द्वारा अपनी सरकार से यह मुतालबा करता हूं कि बैंकिंग में बढ़ती हुई बेइमानियों, लूट खसोट और जो निपोटिज्म और फेवरेटिज्म चलता है और एल० आई० सी० जिसका करोड़ों रुपया गलत तौर पर लगा है और जिस में बहुत ही त्रुटियां आ गई हैं उनके खिलाफ सरकार एक कमिशन मुकर्रर करे ताकि बैंकिंग और एल० आई० सी० की जो गलत बातें हैं उनको किसी तरह से चैक किया जाए।

दूसरी गुजारश यह है कि सारे देश में खाने पीने की चीजों का एक दाम मुकर्रर हो ताकि मुल्क में खाने पीने की वजह से कोई अफरातफरी न हो। गवर्नमेंट एक कमिशन बिठाए जो यह विचार करे कि कन्या कुमारी से लेकर श्रीनगर के आखरी हिस्से तक और उधर आसाम से लेकर गुजरात के आखरी हिस्से तक एक ही कीमत मुकर्रर हो। उसको किस तरह से मुकर्रर किया जाए और किस तरह से गवर्नमेंट उसके लिए सबसिडी दे उसके बारे में कमिशन विचार करे।

तीसरा यह कि जिस मिनिस्ट्री के जेरे साया करोड़ों रुपये के परमिट हर रोज बम्बई में बिक जाते हैं, जिसने करोड़ों रुपये के इम्पोर्ट लाइसेंस बगैर बैंक क्लीयरिंग सर्टिफिकेट जारी कराए, जिसके तहत एक कारखाने और दूसरे कारखाने में एक फेक्ट्री और दूसरी फेक्ट्री में उस तरह का बर्ताव किया गया है जिसमें बड़ा मत-भेद होने की वजह से एक अगर करोड़पति बन गया तो दूसरा बरबाद हुआ, जिस मिनिस्ट्री के तहत ऐसी चीजों के इम्पोर्ट हुए जैसे रेयन का जिसके पर्दे में पुलओवर

[श्री अब्दुल ग़नी]

नये नये कोट और पतलूनें आई हैं उसके टुकड़े आए और वे बिके और जिस मिनिस्ट्री ने पब्लिक इन्ट्रेस्ट के तहत ड्यूटी भी हटा दी उस मिनिस्ट्री से मुतालबा किया जाए कि वह रिजाइन करे। वह कामर्स मिनिस्ट्री है। एक मिनिस्टर जो फारन के, दूसरे मुमालक के मिनिस्टर हैं पहले कामर्स के थे और फिर खाने पीने में आए वहां से फारन मिनिस्टर बने उनके वक्त में करोड़ों रुपया खर्च किया गया बाहर लेकिन हमारी हालत यह है कि जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई कोई भी हमारा मददगार नहीं था, किसी देश में हमारे लिए हमदर्दी के नारे नहीं उठे थे उस को इस नालायकी की वजह से रिजाइन कराया जाए ।

एक और अर्ज करना चाहता हूं आने वाले इलेक्शन में डेमोक्रेसी को जिन्दा रखने के लिए सरकार इस बात का बिल्कुल निश्चय करे कि वह किसी तरह से भी अफसरों को इलेक्शन में सुप्रीम नहीं बनाएगी। अगर बनाएगी तो उससे परेशानी बढ़ेगी।

आज मुल्क में ऐसी बातें हो रही हैं जैसा अभी बस्तर में हुआ। ऐसे इंसिडेंट को जितना भी हो सके सख्ती से दबाया जाए।

काश्मीर की समस्या को हमेशा के लिए हल करने के लिए शेख अब्दुला को रिहा किया जाए शेख अब्दुला की मदद से इस मसले का हमेशा के लिए सुलझाव किया जाए।

मेरी यह भी दरख्वास्त है कि एमरजेंसी को खत्म किया जाए। एमरजेंसी की आज जरूरत नहीं। सब के सब मिल कर इन्दिरा जी के हाथ मजबूत करें। अगर कोई बिल्कुल देश द्रोही है जिससे यह खतरा है कि वह देश को नुक्सान पहुंचा सकता है तो इस पर खुले बंदों मुकदमा चला कर जेल में रखा जाए और जो सख्त से सख्त सजा सरकार देना चाहती है दे।

देश की मजबूती के लिए पोलिस के डिपार्टमेंट को फौज की तरह देश के बचाव की दूसरी लाइन बनाया जाए और पोलिस को सेन्टरल सबजेक्ट रखा जाए ताकि सारे देश में मजबूती आ सके।

एक अर्ज यह है कि जैसे यह हकीकत है कि काश्मीर भारत का है जैसे यह हकीकत है कि इस वक्त सारी दुनिया में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देने में भारत सब से ऊंचा है उसी तरह से यह भी हकीकत है कि हिन्दुस्तान में जो 6 करोड़ मुसलमान बसते हैं वे हिन्दुस्तान का एक अंग हैं। उनके साथ अब ऐसा सलूक हो जिससे उनके मन का यह एहसास कि वह हिन्दुस्तान में बराबरी पर नहीं हैं खत्म हो जाए। मैं एक मिसाल नहीं कई मिसालें दे सकता हूं । बनारस यूनिवर्सिटी में गड़बड़ हुई अलीगढ़ में भी हुई, कुछ लड़कों ने की। मैंने कंडम किया लेकिन दोनों में मतभेद हो । एक यूनिवर्सिटी में एक तरह का बर्ताव हो दूसरी यूनिवर्सिटी में दूसरी तरह का वर्ताव हो तो यह देश को ऊंचा नहीं ले जाएगा, नीचे ले जाएगा।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। जब मुल्क में खाने पीने की चीजों की कीमत एक हो जाए फिर देखा जाए कि चाहे एक चपरासी हो क्लर्क हो आफिसर हो उसके लिए अपना पेट भरने में दिक्कत न हो। अभी तक हम हैल्थ का इन्तेजाम मुल्क में ऐसा नहीं कर सके कि हैल्थ सर्विसिज फ्री दे सकें। जब तक यह नहीं हो जाता उनकी तनख्वाहों की स्केल इस तरह से रखें जाए जिससे आसानी के साथ अपने बच्चों की जिन्दगी को बेहतर बना सकें।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि इन्दिरा जी और इन्दिरा जी के साथी जिन पर देश के चलाने का बोझ है इस बात को खास तौर पर समझ लें कि कोई चाहे वह कितनी ही ऊंची पदवी पर क्यों न हो अगर अब्यूज आफ पावर की वजह से या करप्शन की वजह से या नालायकी की वजह से अलग किया जाता है तो फिर उसको बिल्कुल इसी तरह से ब्लैक लिस्ट किया जाए जैसा कि व्यापारी को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं या किसी बदमाश को ब्लैक लिस्ट कर देते

हैं जो सभा और सोसाइटी के लायक न हो उसी तरह से उनको भी पोलिटिक्स में रेड लाइन कर दी जाए और जिस तरह से वीरेन मित्रा और दूसरे लोगों को फिर मौका देते हैं उनको मौका न दिया जाए।

आखरी अर्ज करता हूं कि इतनी बड़ी बात हुई पंजाब में। क्या कुछ हुआ। हिन्द सरकार के एक मिनिस्टर को डिसमिस किया जाता है। क्यों डिसमिस करते हैं उसको सरकार ही जवाब दे सकती है। फिर उसको मौका दिया जाता है कि वह इलेक्शन लड़े। उसको कांग्रेस का टिकट मिले मुझे इस से बहस नहीं। मेरी अर्ज यह है कि सरकार इस विषय में चाहे जितना बड़ा आदमी क्यों न हो उसके ऊपर वह ऐक्शन ले। उसकी बद-दयान्ती कमज़ोरी या अब्यूज़ आफ पावर की वजह से उसको फिर किसी तरह से भी पोलिटिक्स में आने न दे। जैसे कि अयूब ने बिठा दिया था उन तमाम लोगों को जिन्होंने गद्दारी की थी अवाम के साथ। इसी तरह से उन लोगों को ठंडा कर दिया जाए ताकि इन्दिरा जी का रास्ता साफ हो और वह सफाई के साथ अपने देश को आगे ले जा सकें।]

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI V.C. SHUKLA): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity to clarify certain points which primarily relate to my Ministry. Sir, I think it was hon'ble Mr. P. N. Sapru and, just now, Mr. Ghani who raised the point of the release of Sheikh Abdullah. It has been made clear, Sir, by the Prime Minister— and I want to again restate—that his release is not under contemplation. We are not considering to release him. We are very liberal-minded people. We do not want to detain people unnecessarily. As a matter of fact we released Sheikh Abdullah and Mirza Afzal Beg. But instead of devoting his time to national service or for the cause of this country, Sheikh Saheb went abroad on a Haj pilgrimage and indulged in all kinds of anti-national activities including meeting Mr. Chou En-lai. Sir, we tolerate everything, but there cannot be any compromise regarding the sovereignty and integrity of our nation. Sir, subject to this, we tolerate the most trenchant and unfair criticism. We are not afraid of any criticism howsoever unfair it may be. But when there is any activity which challenges the integrity and sovereignty of our nation, that cannot be tolerated.

شری عبدالغنی : اس پر مقدمہ چلائیے - اس کو موقعہ دیں تاکہ وہ صفائی دے -

†[**श्री अब्दुल गनी** : उस पर मुकदमा चलाइये; उसको मौका दें ताकि वह सफाई दे।]

सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी (पंजाब) : गद्दारों को कैसे मौका दिया जा सकता है।

SHRI V. C. SHUKLA: We have given him a chance. But we have no reason to believe that his earlier stand has changed at all. He is in the same frame of mind and we have no evidence to see or believe that he has changed his line of thinking. And I would request the hon'ble Members that instead of addressing and asking us to release him, they should address themselves to Sheikh Abdullah and ask him to change his attitude and anti-national attitude and become patriotic. There would be no difficulty in releasing him if he adopts the patriotic line which is inkeepiug with the national thinking and the national interest.

Sir, I would request the hon. Members of this House to use their influence with him and change his line of thinking if it is possible for them to do o.

شری عبدالغنی : موقعہ دیں کہ آپ کی تسلی کریں کہ آپ غلط ہیں -

†[**श्री अब्दुल गनी** : मौका दें कि आपकी त t t] Hindi transliteration हैं।]

SHRI V. C. SHUKLA : Then, Sir, I happen to note ihe speech of Mr. Vajpayee in the proceedings of the Rajya Sabha where he has made a mention of the so-called letter which was supposedly written by Pravin Chandra Bhanjdeo to the hon. Home Minister. I am surprised that a responsible leader of an all-India Party should be making such a statement which has no basis. In fact it is absolutely wrong to say that any such letter was ever written by Pravin Chandra Bhanjdeo to the hon. Home Minister and we have checked it up.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa) : On a point of order, Sir. Mr. Atal Bihari Vajpayee has alleged that a letter was received by Shri Gulzarilal Nanda, the Home Minister. Would it be right for the Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs to come here and say that Mr. Gulzarilal Nanda did not receive that letter ? He must do it himself because in case a privilege motion is brought against Shri Gulzarilal Nanda, he would take shelter under the plea that he had never said anything like that in this House and that there was no letter written to him The hon. Deputy Minister also would get out of it then.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : Mr. Misra, I may cut short your argument. I am informed that Mr. Vajpayee has already been informed by the Home Minister about the allegation made by him.

SHRI LOKANATH MISRA : Then it is all right.

SHRI V. C. SHUKLA : There is no question of my getting out of it, Sir. We do not act like Swatantra Party Members. Therefore there should be no apprehension of that kind. And I repeat it once again. As you have kindly observed, the Home Minister has already informed Mr. Vajpayee and this gentleman should be more careful in future before making such statements here in this House.

One Member, Mr. Devi Singh, mentioned that a Memorandum was submitted by M.L.As. and M.P.s against the Chief Minister of Rajasthan and he alleged that no enquiry was made and no attention to that Memorandum was given. 1 must say that most careful attention to that Memorandum was given and all possible enquiries were made but even a *prima jacie* case could not be made out against the Chief Minister on the basis of that Memorandum. So the matter was not proceeded with further and it had to be dropped. It is well known that if it is necessary to take action against any Chief Minister or anybody else, howsoever highly placed, we have never hesitated in taking that step or ordering that enquiry. It can be seen if you go through the record for the last three or four years. But there must be some *prima jacie* case for doing so.

Mr. M. N, Kaul made certain references regarding the administrative reforms that are very necessary. This is a well-acknowledged fact and we also subscribe to this view that administrative reforms are very necessary and the Government have recently appointed the Administrative Reforms Commission and most of the points that Mr. Kaul raised have been referred to this Commission. I am quite sure Mr. Kaul will get in touch with the Commission and also give them the benefit of his ideas and views.

Mr. D. L. Sen Gupta said something about two Congressmen who are members of the Calcutta Telephone Advisory Committee, that they are indulging in all sorts of things. Well, at present we have no information about it and I do not believe this could be true but if it is so, it would be an exception. In the case of most other parties it could be a rule. I do not say it is so, but I am quite sure that such . . .

SHRI LOKANATH MISRA : Do you mean political parties ? If that is so, then it is highly objectionable. Sir, he must withdraw it.

SHRI V. C. SHUKL V : if they make allegations against my Party, I have also got a right to make allegations against them.

SHRI LOKANATH MISRA: You must withdraw it. Sir, he said in the case of other political parties it is a rule and it is an exception in the case of the Congress Party.

SHRI V. C. SHUKLA : I said it could be. You can say that but you cannot take away my liberty.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : What I heard was "it could be".

SHRI MULKA GOVIND \ REDDY (Mysore) : Sir, let him not accuse others.

SHRI LOKANATH MISRA : Your Party would be indulging in all sorts of abuses.

SHRI V. C. SHUKLA : Sir, I would lik« to make one appeal to the hon. Members here. Let them not attack people who are not in the House to protect themselves. *(Interruption)*

This is all I have to say and if there are any other points which concern my Ministry, we can write to Members personally. Thank you very much, Sir.

श्रीमती श्याम कुमारी खान (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है हिन्दुस्तान में, और मैं आपका ध्यान गोपाल कृष्ण गोखले की सैन्टेनरी की तरफ दिलाती हूं, आज उनकी जन्मशती का दिन है और मैं आपकी इजाजत से इस सदन की तरफ से और अपनी तरफ से अपनी श्रद्धांजलि उनकी स्मृति में अर्पण करना चाहती हूं ।

شری عبدالغنی : بے شک ہم سب اس میں شامل ہیں ۔

†[**श्री अब्दुल गनी** : हम सब उसमें शामिल हैं ।]

श्रीमती श्याम कुमारी खान : महोदय, यहां पर तीन दिन से हम लोग तरह तरह की बातें यहां से सुन रहे हैं, हमको यह बताया जा रहा है कि हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट की क्या-क्या त्रुटियां हैं, कहां-कहां हमने गलतियां की हैं, और यहां तक कहा गया है कि हम एक पैसा भी खर्च करने के हकदार नहीं हैं, ये सब बातें चल रही हैं लेकिन मेरा दृष्टिकोण थोड़ा-सा अलग है । मैं आपको याद दिलाती हूं कि आखीरी 12 महीनों में इस मुल्क के ऊपर बड़ी घनघोर घटायें छाई हैं, इस मुल्क में बीसवीं सदी की महाभारत की लड़ाई भी लड़ी गई है और उसके बाद कुछ ऐसे मसले पेश आए हैं जिन पर मैं अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री का ध्यान दिलाना चाहती हूं । लड़ाई के बाद मिनिस्ट्री आफ डिफेंस ने उन बहादुर जवानों और अफसरों के खानदानों के लिये हर तरह के रुपये का प्रबन्ध किया लेकिन मैं यह नम्र निवेदन करना चाहती हूं कि केवल रुपये के प्रबन्ध से इंसान का जीवन पूरा नहीं होता, आसान ज़रूर हो जाता है लेकिन जीवन में और चीजों की भी ज़रूरत होती है । जिन जवानों ने अपनी जानें दे दीं हैं और जिनके बिछुड़े हुए बच्चे और बेवायें रह गई हैं वे बेवायें इस बात के ऊपर गर्व करती हैं कि उनके पति ने अपने देश के लिये अपनी जान अर्पण की । हम यह चाहते हैं कि उनके लिये किसी किस्म की संस्थायें खोली जाएं जहां वह अपने जीवन को सफल बना सकें । केवल पैसा ही उनको राहत नहीं देगा, उनको तभी राहत मिलेगी जबकि वह अपने देश की कोई सेवा कर सकें । इधर मुझे ध्यान दिलाना है ।

इस लड़ाई की वजह से एक और समस्या खड़ी हो गई है । हमारे जवान और हमारी फौजें सब सीमा पर हैं, सीमा से उनको हटाना आसान नहीं है और न यह मुनासिब होगा । उन सब जवानों और उन सब अफसरों के बीबी बच्चे बिछुड़े हुए हैं । इसकी बहुत सख्त जरूरत है कि उन बिछुड़े हुए खानदानों के लिये भी इंतजाम किया जाय और इसको प्रायरिटी नम्बर 1 दी जाय । उनके खानदान ऐसी जगह बसाये जायें जहां कि जवान और उनके अफसर और उनके कुटुम्ब वाले मिल सकें । अपने खानदानों के वक्तन फवक्तन और वहां पर हर तरह की सुविधा, शिक्षा आदि की, दी जाय । ये दो बातें मैं रक्षा मंत्री के सामने पेश करना चाहती हूं ।

t[ ] Hindi transliteration.

[श्रीमती श्याम कुमारी खान]

शिक्षा के मसले के ऊपर जब आती हूं तो हम सब को इस बात का बहुत इत्मीनान है कि प्राइमरी एजुकेशन में हमारे मुल्क में पिछले वर्षों में काफी तरक्की हुई लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रौढ़ शिक्षा में हम लोग पिछड़ गये । हमारे जो आंकड़े हैं वह यह दिखलाते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा जो पांच वर्ष पहले थी वह अब नहीं है और वह कम होती जा रही है । इसकी तरफ हमें ध्यान देना जरूरी है क्योंकि बगैर शिक्षा के इंसान को कोई जानकारी नहीं हो सकती । बहुत रुपया इस मुल्क का बच सकता है अगर हम प्रौढ़ शिक्षा चलायें और प्रौढ़ शिक्षा की मार्फत हम अपने सब प्रोग्राम देश के सामने पेश कर सकें ।

एक और बात के ऊपर ध्यान दिलाना है । आज आप जानते हैं कि इस वक्त आर्थिक समस्या काफी कठिन है, जो पैसे वाले लोग हैं उनको भी कठिनाई हो रही है और इसलिये यह जरूरी हो गया है कि जहां 18 वर्ष का बच्चा हुआ वहां उसने काम करना शुरू कर दिया और जब बच्चा काम करना शुरू कर देता है तो उसकी तालीम पर असर हो जाता है । हम जानते हैं कि दिल्ली के अन्दर करेस-पांडेंस कोर्सेज और कोर्सेज के मार्फत बच्चों का इंतजाम कर दिया गया है कि वह आगे पढ़ें लेकिन हम यह भी जानते हैं कि युनि-वर्सिटी की तालीम बहुत महंगी हो गई है, मामूली आदमी के इमकान के बाहर है कि वह युनिवर्सिटी की एजुकेशन दिला सके, इसलिये मैं अर्ज करना चाहती हूं कि सारे हिन्दुस्तान में यह फैलाना है और हर युनिवर्सिटी से कहना है कि वह एक या दो कोर्सेज ऐसे जरूर रखें जिसमें कि काम करने वाले बच्चे ही नहीं बल्कि बूढ़े भी अपना फ्युचर और अपना भविष्य बढ़ा सकें और ज्यादा तालीम हासिल कर सकें । तालीम हासिल करना जरूरी है । यह इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारा प्रचार जो है वह बहुत कमजोर है । हमारा जो प्रचार है हमारी जो पब्लिसिटी है वह बाहरी ही कमजोर नहीं है क्योंकि इस सदन के अन्दर व्याख्यान दिये गये हैं कि एक्स-टर्नल पब्लिसिटी ने लड़ाई के वक्त बहुत कमजोरी दिखलाई है । मेरा कहना यह है कि हमारी जो इन्टर्नल पब्लिसिटी है वह भी कमजोर है । हम यह नहीं कहते कि हमारी सरकार मेहनत नहीं कर रही है, प्लान नहीं बना रही है । सरकार प्लान बना रही है और शिक्षा मंत्रालय शिक्षा के तरह-तरह के तरीके दिखा रहा है, लेकिन प्रचार की बेहद कमी है । अगर प्लान्ड पब्लिसिटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें यह लिखा हुआ है कि जब तक हमारा प्रचार ठीक नहीं होगा तब तक हमारे मुल्क के बाशिन्दे को यह मालूम नहीं हो सकेगा कि वह किस तरह से और कहां से मदद ले सकते हैं । वे किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं । इस बात का—इतमिनान है कि पिछले साल हमारे मुल्क के ऊपर जो काली घटा छा गई थी, उसके बावजूद हमारे नेताओं की मेहनत की वजह से, उनके हरीकेन टूर की वजह से हमारे देश का अन्तर्रा-ष्ट्रीय कोआपरेशन बहुत बढ़ गया है । मैं चाहती हूं कि यहां पर मैं आपके सामने यह निवेदन करूं कि पिछले साल अन्तर्राष्ट्रीय कोआपरेशन का साल था, लेकिन यहां पर कुछ लोगों ने स्पीच दी है और उसमें उन्होंने अमेरिका के ऊपर खास तौर पर छींटा डाला है कि वे क्यों हमारी तालीम में शरीक होते हैं और क्यों "इंडो यू० एस० कोआपरेशन" होता है । तालीम जो है, मैं अर्ज करना चाहती हूं कि उसकी कोई सीमा नहीं होती है । दिमाग के कामों में और साइन्स के अन्दर मुल्कों में सीमा नहीं हो सकती है । उसके अन्दर चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे इंग्लैण्ड हो, हरएक का कोआपरेशन हम ले सकते हैं । यह हमारे ऊपर इतमिनान हो जाय कि हम इस देश के निवासी हैं और हमें स्वदेशी पसन्द है, हम को यहां की संस्कृति का खयाल है । हम लोग ऐसे नहीं हैं कि हम अपनी संस्कृति को, अपने देश को और हर चीज़ को लुटा देंगे अगर अमेरिका का इन्फलुएन्स हो जाय ।

मैं अर्ज करना चाहती हूं कि आज हालत क्या है और बगैर इस इंडो यू० एस० कोआपरेशन के भी हमारे लोग किधर जाना चाहते हैं ? आज हमारे बच्चे तालीम के लिए किधर जाना चाहते हैं। वे अमेरिका की तरफ जाना चाहते हैं, वे इंग्लैण्ड की तरफ जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं ? इसलिए नहीं कि अमेरिका में कोई खास चीज है, बल्कि इसलिए कि वे यह समझते हैं कि वहां पर जाने से वे तालीम से फायदा उठा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम उनको वही सुविधा दें, वही तालीम दें, इसीलिए यह सहयोग, सम्पर्क और कोआपरेशन कर रहे हैं और इसकी वजह से गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट देखेगी कि वह इस कोआपरेशन से अमेरिका के हाथों में बिकने जा रही है तो वह उसको तोड़ देगी।

इस समय विदेशी मुल्क हमारे लिए बहुत चिन्तित हो गये हैं और उन्होंने खाद्य समस्या में हमें जो सहयोग दिया है उसके लिए हम आभारी हैं। मैं यह बात जानती हूं कि हम हमेशा के लिए खाने के बारे में दूसरे मुल्कों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। मैं यह भी जानती हूं कि दूसरे मुल्क जो हैं वे हमारे पास दरख्वास्त लेकर नहीं आये हैं कि तुम मेहरबानी करके हमारा खाना ले लो, या रुपया ले लो। हमको उनके खाने की और रुपये की जरूरत है और हम यह महसूस करते हैं कि यह रुपया और खाना जो हम ले रहे हैं वह थोड़े ही दिनों के लिए है क्योंकि हम इस बात को महसूस करते हैं कि हमें अपना खाना बढ़ाना है, हमको अपना रुपया बढ़ाना है और विदेशी पूंजी के ऊपर हम हमेशा के लिए भरोसा नहीं कर सकते हैं।

भुखमरी के बारे में जो बातें कहीं गई हैं, उसके बारे में मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि यह बहुत जरूरी है कि हर पार्टी को मिल कर इस बारे में काम करना चाहिये और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं तो रचनात्मक कार्य करनेवाली औरत हूं और मैं हर पार्टी का सहयोग चाहती हूं। लेकिन मैं अपने विरोधी भाइयों से पूछना चाहती हूं कि वे सब चीज कांग्रेस के ही ऊपर क्यों छोड़ना चाहते हैं और वे खुद कोई संस्था खड़ी क्यों नहीं करते जिसके जरिये उड़ीसा में या किसी दूसरी जगह वहां पर भुखमरी फैली हो, वहां जाकर लोगों की सेवा की जा सके। मैंने अभी जाकर हर भाई से पूछा कि उड़ीसा में जो यह हालत बयान हुई है वह कहां तक सच है। इससे मुझे बहुत शर्म आई जो वाजपेयी जी ने कहा कि उड़ीसा के अन्दर सहायता के लिए कोई संस्था काम नहीं कर रही है। लेकिन मुझे यह बतलाया गया है कि उड़ीसा के अन्दर कांग्रेस आर्गनाइजेशन काम कर रहा है और उसके लोग उन एरियाज में जा रहे हैं जहां भुखमरी फैली हुई है। लेकिन वहां पर कोई और संस्था नहीं है। मैं उड़ीसा जाने वाली हूं और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूं कि जहां तक उड़ीसा के बच्चों का ताल्लुक है, उनका जिम्मा इंडियन कौंसिल आफ चाइल्ड वैलफियर आर्गनाइजेशन ले लेगी। मैं अपने विरोधी भाइयों से कहना चाहती हूं कि मेरा और तुम्हारा यह काम है कि इस भुखमरी को बन्द करें और इसके लिए हमें पार्टी का सवाल सामने नहीं लाना चाहिये। आप यह नहीं चाहते हैं कि कि यह मुल्क मरे और न हम ही चाहते हैं कि इस तरह की कोई बात हो। जहां तक राजनीतिक सवालों का ताल्लुक है हम राजनीति के ही अन्दर जरूर एक दूसरे को पछाड़ सकते हैं। इस समय इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं इसकी वजह से जरा तनाव ज्यादा है, इसको मैं महसूस करती हूं। लेकिन जहां तक राजनीति का ताल्लुक है, उसको हम जानते हैं।

दूसरा एक नम्र निवेदन मैं अपनी सरकार से यह करना चाहती हूं कि जहां खाने का मामला है, शहरों में काफी अनाज है। यहां हम रुपया लेकर, मदद लेकर अपने गांवों में बांट रहे हैं, वहां हमारा यह भी फर्ज हो जाता है कि हम शहरों का वातावरण भी बदलें।

[श्रीमती श्याम कुमारी खान]

शहरों में जो रहते हैं उनका यह फर्ज हो जाता है कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, हम उनकी फूड हेबिट्स (Food habits) को बदलें । इस मामले में हम हर संस्था की मदद कर सकते हैं जो कि खाद्य समस्या को हल करने के लिए काम कर रही हैं और हर तरह का अनाज बचा सकते हैं । लेकिन मैं जानती हूं कि हम इस तरह से गेहूं बचाकर पूरे गांव का पेट नहीं भर सकते हैं । हिन्दुस्तान के अन्दर हमेशा से यह चला आता है कि जो शहरवाले करते हैं, जो बड़े आदमी करते हैं, जो शिक्षित लोग करते हैं, जो विद्वान लोग करते हैं, उनको देखकर छोटे-छोटे लोग, अनपढ़ लोग, गरीब लोग भी उसी तरह की बात करते हैं क्योंकि उनमें एक अजीब तरह की श्रद्धा पैदा हो गई है । इसलिए मैं अपने शहर के भाइयों से जरूर कहूंगी कि वे अनाज जमा करें और जो समाजसेवी संस्थाएं हैं उनसे भी कहें कि वे भी अनाज जमा करें । गवर्नमेंट इस बात की सुविधा दे कि वह जगह बताये जहां अनाज जमा किया जा सकता है जब तक यह नहीं होगा इस तरह का कोई काम शहरों में नहीं किया जा सकता है । हम कांग्रेस वाले कोई नहीं चाहता है कि हमारे लोग बैठे रहें और कोई संस्था इस तरह का काम करे । हमारे ऊपर, इस तरह के आरोप लगाये जाते हैं कि हम काम नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि लोग भूखे मर जाएं और आप लोग कहते हैं कि हमारी पालिसी की वजह से ऐसा हुआ है । लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूं कि गवर्नमेंट की इस तरह की पालिसी नहीं है और न उसे इस तरह की पालिसी की जानकारी ही है जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो ।

हमारे भाई श्री चन्द्रशेखर ने परसों बतलाया कि इस मुल्क की समस्याओं का हल नहीं हो सकता है जब तक कि परिवार नियोजन न हो । हमारे भाई ने उस वक्त आगे बढ़ कर यह भी कहा कि एबोरशन (Abortion) बहुत जरुरी है और इसकी कानूनी तौर पर इजाजत दे दी जानी चाहिये । मैं उनके सामने यह पेश करना चाहती हूं कि एबोरशन की, कानूनी तौर पर खास हालतों में ही इजाजत अब भी है । लेकिन इससे बढ़कर तो यह बात देखनी है कि इस समय हमारे अस्पतालों की हालत क्या है, जो हमारे डाक्टर हैं उनकी हालत क्या है और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि एबोरशन की इजाजत बगैर कैदों के हो जाय । मैं खुद परिवार नियोजन के बारे में बहुत सख्त काम करती हूं और हर वक्त उसको आगे बढ़ाती हूं । लेकिन एबोरशन को हम आगे तभी बढ़ा सकते हैं जब हमारे अस्पतालों की हालत फर्स्ट क्लास हो, जब हमारे मामूली आदमी के लिए भी आपरेशन का ठीक तरह से इन्तजाम हो जाय । हम ऐसी चीजें देश के सामने नहीं रख सकते हैं जिसमें हम उन्हें अच्छी तरह से सुविधा न दे सकें । अगर हमने इस तरह की सुविधा का इंतजाम नहीं किया तो हमारी कितनी ही औरतें मर जायेंगी । (*Time bell rings.*)

May I have another 5 minutes?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA) : Try to finish in two or three minutes.

SHRIMATI SHYAM KUMARI KHAN : Yes.

एक बात मैं और अरज करना चाहती हूं और वह यह है कि जब तक हमारी शासन प्रणाली ठीक नहीं होगी, देश में एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम ठीक नहीं होगा, तब तक हमारा कोई काम ठीक नहीं हो सकता है । मैं दो बातें होम मिनिस्ट्री के सामने रखना चाहती हूं । नम्बर एक । मैंने हमेशा से यह ख्याल किया है कि जो आल इंडिया सर्विसेज हैं, वे कई एक हैं । लेकिन उसमें भी ग्रेडेशन है तनख्वाहों में, चाहे सर्विसेज आल इंडिया हो । आई० एफ० एस० का कोई ग्रेडेशन होता है, आई० ए० एस० का कोई ग्रेडेशन होता है, रेलवे का कोई ग्रेडेशन होता है, पुलिस का कोई ग्रेडेशन होता है और इसका नतीजा यह होता है जहां बहुत ऊंचे ग्रेड होते हैं, वहां

पर लोग बहुत खुश हैं । और जिन लोगों के ग्रेड ऊंचे नहीं हैं उनको हर वक्त एक इन-फीरियरिटी काम्प्लेक्स रहता है । लेकिन मैं यह विचार पेश करना चाहती हूं जो कि और लोग भी पेश कर चुके हैं कि Grades of pay (तनख्वाहें) एक सर्विस की एक ही हों और ये दो-दो तीन-तीन लेविल्स नहीं होने चाहियें ।

3 P.M.

मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम पर यह कहना है कि यहां पर सदन के अन्दर कई दफा यह सुनाई पड़ा है कि फारेन सर्विस के जितने लड़के हैं वे बिलकुल काम ठीक नहीं करते हैं और वे विदेशियों से ज्यादा विदेशी हो गये हैं और वे हिन्दुस्तानी नहीं रह गये हैं । मेरा निवेदन यह है कि फारेन सर्विस में लोग ठीक काम तब कर सकते हैं जब आप उनको यह सुविधा दें कि वे वापस हिन्दुस्तान में आ कर कुछ काम कर सकें । 24 या 25 वर्ष की आयु का लड़का डेढ़ साल की ट्रेनिंग के बाद छः वर्ष के लिये विलायत भेज दिया जाता है । अब सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि विलायत का उसके ऊपर असर हो जब तक आप उसको यह मौका न दें कि जब वह वापस आये तो उसका रिओरियन्टेशन हो, वह केवल वापस दिल्ली शहर में न जाये बल्कि वह हिन्दुस्तान के गाँवों के लोगों में जाये तब तक उसको कैसे गांवों का प्रचार करना आ सकता है ।

समाज कल्याण मिनिस्ट्री को ढाई वर्ष हो गये । ढाई वर्ष से मुझे यह कहना पड़ता है कि समाज कल्याण के कार्यकर्ता जो हैं वे एक अजीब दुविधा की हालत में हैं । उनकी समझ में नहीं आता है कि समाज कल्याण क्या है और समाज कल्याण के माने क्या हैं । इसमें कोई शक नहीं है कि अगर समाजवाद होना है, अगर प्रजातन्त्र होना है तो जितने बाशिन्दे हिन्दुस्तान के हैं उनका सहयोग मिलना हमें बहुत जरूरी है । ट्राइबल्स के बारे में आपने देखा कि मध्य प्रदेश में क्या तमाशा हुआ है । राजनैतिक तौर से बहुत कुछ यहां पर कहा गया है । लेकिन क्या यह भी कोई सोचता है कि यह जंगल का शेर क्यों जागा । यह जंगल का शेर जो उठ गया, यह जरूरी था उठना इसलिये कि हमने उसकी काफी सेवा नहीं की और मुझे खाली इस तरफ ध्यान अपनी गवर्नमेंट का दिलाना है ।

और सब लोगों ने, इधर से भी और हमारे विरोधी भाइयों ने भी, यह पेश किया है कि हमारे मुल्क के ऊपर इस वक्त बड़ी घोर समस्याएं छाई हुई हैं । मेरे भाई वाजपेयी जी ने कहा कि 47 करोड़ जनता में आशा पैदा करनी है । आशा हम कैसे पैदा कर सकते हैं ? मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है गवर्नमेंट हर तरह से कोशिश करेगी कि वह आशा ही न पैदा करे बल्कि वह हर तरह से अपने देश का स्तर ऊंचा करे । पांच साल के अन्दर इस देश ने क्या-क्या नहीं देखा । पांच साल के अन्दर हमने दो प्राइम मिनिस्टर्स की मौत देखी । पांच साल के अन्दर हमने दो लड़ाइयां देखीं, एक में हम आग से जले और दूसरी में हम खाक में मिले । दोनों लड़ाइयां हमने लड़ी, काफ़ी घायल हुए, लेकिन तब भी हम खड़े हुए हैं । इस वक्त की जो समस्याएं हैं वे मामूली नहीं हैं । लेकिन मेरा कहना यह है कि एक देश को उठाना आसान काम नहीं है । मैं आप को कवि की एक लाइन सुना कर खत्म कर देना चाहती हूं :

बस्ती बसाना खेल नहीं,
बस्ते बस्ते बस्ती है ।

DR. B. N. ANTANI (Gujarat) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to make a few general observations on the Appropriation Bill. I do it keeping in mind the advice which used to be given frequently by the late Gopal Krishna Gokhale to those who offer criticism on such Bills: co-operate where you can, criticise where you must. Bearing that principle in mind I place before this House the test to justify appropriation of such a huge sum out of the Consolidated Fund of India for the Services. Do the Services give equivalent return for the appropriation

fDr. B. N. Antani] of this huge amount? The justification for voting this huge amount will be the standard and efficiency of the Services. The people from whom the amount is collected have, 1 believe, a right to demand the answer. The answer has been given by the Prime Miniter herself when she recently said:

"The problem of Administration has added to the difficulties of the country all along the line".

"The Administration has deteriorated at the Centre, in the States and even in the lower rungs of the Government set-up." The condition of the Services being such, how are we going to justify this Appropriation Bill? She has also said:

"Political freedom by itself has little meaning. It has to be defended against economic pressures and exploitation. It has to be made meaningful by creating conditions for a better life for the people".

On this standard how can we justify this Appropriation Bill—which is before this House? For instance, what are the services giving? Do they give equivalent return to the country? Take, for instance, the huge amount proposed to be appropriated to the External Affairs Ministry. We have been sending our gentlemen abroad to look after the interests of Indians domiciled elsewhere. I come from East Africa where I had the privilege of spending about 30 years of my life from 1910. There has been a recent revolution in Zanzibar which is now known as Tanzania. There our Indians were massacred; they were looted and sent to India. Our Government, our External Affairs Ministry, our agents there could not find even sufficient ships to send our people here whereas a British man-of-war was standing by to take half a dozen of their people back and two others to take other nationals to their countries. Our people were left without any resources. Even today when repatriation has come about, when people are coming to India, they are not given the protection that they desi e. Sir, what is the test of recruiting these gentlemen in the Foreign Service? I was told that the person should be handsome with a charming wife for social manners. He may have that but the main purpose of looking after the people and giving protection to them is not served at all. I remember a case.

Only a week back a young boy. came here from Magadiso Somalia. He came here with a valid passport. When he wanted to return to that country where he had been domiciled and settled in business for centuries—his father was in business there—the Government concerned gave him the permit but our Passport authorities refused it without disclosing any reason. That person went to a Member of the Lok Sabha from Kutch who wrote to the External Affairs Ministry and the reply was that the Passport could not be given. For God's sake, disclose the reasons. If he was an undesirable person, tell us and we shall deal with him as such.

Similarly, when people come here from Zanzibar they bring some cloves which is authorised to be brought here up to the value of Rs. 10,000 or so but the excise authorities, the customs authorities go after them. Cases after cases are filed and there is nobody to protect them. As the time allotted to me is short I will not dilate on this but this question requires to be gone into very very carefully by the External Affairs Ministry.

Take again the instance of Chhad Bet road in the Kutch border; from 1956 nothing was done. When the attack came the attention of the External Affairs Ministry was drawn to the wretched condition in which the borders were being maintained. We woke up only when the attack came and now when the horses have lefi the stable is going to be locked. Now we propose to spend through C.P.W.D. enormous amounts of money for this but look at the condition in which the roads axe being constructed; look at the way in which it is being done. My heart bleeds when I see this sort of indifference and inefficiency on the part of the authorities for whom we are going to vote his Huge amount. Look at the condition of the Narmada project. The Khosla Committee Report has been there for three years. Because the Gujarat Government is patient, because the Gujarat Government is behaving in a gentlemanly manner, arl these qualities are construed as weakness and the Ministers of the Gujarat Government are being shunted from pillar to post, one day to see the Central Minister, one day to , see the Minister of Madhya Pradesh and I Maharashtra also coming in the way. Why

are all these things done, when we are talking of integration? Is this integration? The late Sardar Vallj.bhbhai Patel collected scattered pearls of India, 562 of them, made them into a wreath, but he put it in the neck of monkeys who did not know the value of these pearls. They began to chew it and it came to its logical conclusion. You make Subas after Subas and who knows what will h ippen tomorrow and who will not ask for a Suba? I say Kutch should be made into a Suba and I shall fast unto death and the Suba shall be given! God said heaven shall be made and heaven was made!

SHRI G. H. VALIMOHMED MOMIN (Gujirat): Havd that courage.

DR. B. N. ANTANI: Courage I have not got to learn from you. So, what I feel is that it is the vacillation, it is weakness of the Centre, which is going to undo what we have been trying to do for the last eighteen years. We have accepted a federal pattern of government. If the Centre is not strong, if the Centre is not vigilant, If the Centre is not firm, then the comport m parts will be behaving in the way they do and the phenomenon has been described by the previous speakers. So, I shall not waste the time of this hon. House on this. On the contrary, what I feel we should do about these Services is this. Vigilance and efficiency on the part of the Centre are the most cardinal principles that are necessary. I concede that for a developing country, expenditure is necessary, but the justification is in the results that we are having. Are we having that? I shall read out to you from a recent Report of the Estimates Committee on the National Physical Laboratory. On page 135 it says:

"The Committee regret that a large number of scientists have left the National Physical Laboratory during the last four years, thereby adversely affecting the progress of research work in the laboratory. The Committee feel that this my partly be due to lack of proper scienlific atmosphere in the laboratory. The Committee would urge that National Physical Laboratory should immediately take remedial measures to retain the scientists engaged in specific prejjets so that the important research proj:cts which were being carried out by these scientists, may continue with, it interruption."

Then, the Report says:

"It appears that all was not well in the N.P.L. with the result that quite a large-number of scientists and research fellows have left the Laboratory. They hope that the C.S.I.R. will make a proper study into the causes of so many desertions." Even in a matter like scientific research and progress if the Estimates Committee has to report in this manner, how is the Appropriation Bill justified? I humbly submit that I know that with this majority, with this brute majority, by attacking the Opposition in this way, you can pass this measure. There is absolutely no tolerance on the part of the Treasury Benches, when a senior Member like Mr. Sapru rises to say something which is unpleasant, he is also interrupted. It is the continued toxin of power for eighteen years. It is the conceit in their heads. They should not have behaved in this wcy and presented *v.n* Appropriation Bill of this nature. Thty have got a giant's strength. It was Gepal Krishna Gokhale, who once told Lord Curzon, who was presiding over the Imperial Legislative Council. He WPS in the Opposition and he exhorted: "Your Excellency, you have got a giant's strength, but Shakespeare said: How nice it is to have a giant's strength and how tyrannical it is to use it as a giant." I, therefore, appeal to this House to be tolerant towards the Opposition. This is a democratic a -i i In a democratic set-up, if the Opposition tells you something unpleasant, please listen to them. We have been listening to you, w have been seeing what ycu hrve been doing for the past eighteen yer.rs. Why cannot you have tolerance to listen even for a few minutes? With these words, as time is very short, I only submit that there is "Dalnli" going on. Go through the revenue records of so many districts. I challenge you. Nearly 80 per cent of them are faulty. Look at the Panchayati Raj. Panchayati Rrj is something with a noble conception with noble principles. We thought of this idea and introduced it in so many States. I have been a witness and I have been comparing it in my own way. If a father or mother sent the priest to find out a bridegroom of eighteen years for their eligible daughter, the priest could not find an eigh-

[*Dr.* B. N. Antani] teen-year boy. He brought two of nine-years each. Similarly, this Panchayati Raj has been working. The work between the Collector and the DDO has been bifurcated, instead of it being co-ordinated and in the name of co-operative societies ; nd in the name of Panchayati Raj, what sins are not being Committed? The thumb impression of the \illige Sarpanch is sufficient for any sin. What a harm is being done to the country? Therefore, this is of the utmost importance—the Opposition urges this in a spirit of co-operation, not in a spirit of destructive criticism, as some of them think—, and with these words, if I can inspire them, if I can create a feeling—which is a hopeless task—if 1 have set them rethinking, then and then only this Appropriation Bill will have been justified.

Thank you.

श्री आर० पी० खेतान (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस सदन में अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया । जनता को खाना, कपड़ा, रहने की जगह, दवा-दारू और शिक्षा आदि की आवश्यकता होती है जिनमें पहला स्थान खाने का है । इसकी व्यवस्था करने के लिए सबसे पहला जरूरी कदम यह हो जाता है कि इसकी पैदाइश हमारे मुल्क में हो जिससे कि बाहर से अनाज मंगाने की आवश्यकता न पड़े । जो देश खाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता है वह देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है । किसी कारण से बाहर से समय पर अनाज न आ सके तो भूखों मर जाना पड़ता है । आज भी आप देखेंगे कि कुछ प्रान्तों में इस तरह की मौतें हुई हैं जिनका इस सदन में जिक्र हो चुका है । यह भी सत्य है कि हमें बाहर से खाद्य मंगाना पड़ता है । इसलिए अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए अविलम्ब प्राथमिकता दे कर कार्य-वाही करनी चाहिए । पैदावार बढ़ाने के लिए जमीन की जरूरत है । वह तो भारत में कृषि प्रधान देश होने के नाते पर्याप्त मात्रा में है ही, पर उसका उपयोग अपर्याप्त साधनों के कारण पूरा हो नहीं पाता है और इसलिए पैदावार नहीं बढ़ रही है । आजादी के बाद के 18 बरसों में इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, नहीं तो क्या कारण है कि जब दूसरे देशों में यहां के मुकाबले में ज्यादा पैदावार होती है तो यहां पर न हो ? खाद की कमी और सिंचाई की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण ही ऐसा लगता है कि जरूरत भर की पैदावार नहीं हो रही है । जिन गावों में पानी के लिए कुवें, नहर ट्यूबवेल आदि नहीं हैं, उनके लिए योजनाएं तो बनती हैं, पर वे कागजों पर ही रह जाती हैं । उनको कार्य रूप में परिणत करने में इतना समय लग जाता है कि वे सफल नहीं होतीं और खर्च भी ज्यादा बैठता है । माननीय मंत्रियों को दूसरे जलसों और स्वागत समारोहों से फुरसत नहीं मिलती कि वे ग्रामों में गरीबों और किसानों के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनके दुख-दर्द को मिटाने की चेष्टा करें और पैदावार बढ़ाने में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करें । पैदावार बढ़ाने के लिये हमें खाद की जरूरत है जिसकी देश में कमी है । इसके लिये हमें खाद बनाने के कारखाने बढ़ाने होंगे । इन कारखानों के लिये आवश्यक मशीनें आदि हमें अमरीका हो, रूस हो या और कोई देश हो, जहां कहीं से भी मिले, शीघ्रातिशीघ्र मंगानी चाहिये । इसमें कुछ वामपंथी लोग रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं, उनका मकसद देश के हित में नहीं है ।

जहां-जहां खेती के लिये आवश्यक साधनों की जरूरत है वहां-वहां अनुसंधान करके उनकी व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि पैदावार बढ़ सके । किसानों को पर्याप्त मात्रा में ऋण भी दिया जाना चाहिये तथा उनको उनकी फसल का उचित दाम भी मिलना जरूरी है । सिंचाई की व्यवस्था के लिये बिजली आदि की भी उन्हें पूरी सहूलियत मिलनी चाहिये ।

यह खाद्य का प्रश्न ऐसा है जिसमें सभी पार्टियों एवं व्यक्तियों का सहयोग ल कर सरकार को चाहिये कि अविलम्ब ऐसी घोषणा करे कि अगर वह एक निश्चित समय में जनता को पूरा खाना नहीं दे सकी

तो वह त्याग-पत्र दे देगी। यह घोषणा उस तरह की नहीं होनी चाहिये जैसी कि लगभग तीन वर्ष पहले श्री नन्दा जी ने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में की थी; तभी जनता को विश्वास होगा अन्यथा नहीं ।

हमें खेद है कि जो कुछ पैदा भी होता है और बाहर से जो मंगाया जाता है उसके वितरण की व्यवस्था भी ठीक नहीं है । नहीं तो क्या कारण है कि एक जगह तो बढ़िया गेहूं बीस रुपये मन मिल रहा है दूसरी जगह उससे घटिया गेहूं का पचास रुपया लग रहा है । इसके लिये सभी पार्टियों व प्रायः सभी सदस्यों ने एकमत से अनाज का जोन खत्म करने की मांग की परन्तु सरकार तो अपने अफसरों की बातों पर ही ज्यादा ध्यान देती है, संसद्सदस्यों की नहीं । अगर मंत्रिगण और सरकार विधायकों की बात न सुन अपनी मनमानी ही करें तो फिर इन सदनों को इतना खर्च कर के रखने की जरूरत ही क्या है ? यह तो सिर्फ ऐसा लगता है कि जनतन्त्र का मजाक उड़ाया जाता है । व्यापारी वर्ग यदि थोड़ी सी गलती कर देता है तो उसे डि० आई० आर० में पकड़ कर बन्द कर दिया जाता है । और ये मंत्री महोदय लोग बड़ी से बड़ी भूल करते हैं उसके बावजूद भी उन लोगों से कुछ नहीं पूछा जाता। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि उनको भी डी० आई० आर० में पकड़ कर क्यों नहीं बन्द किया गया ?

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां शिक्षा भी दिनोंदिन महंगी होती जा रही है। पर्याप्त संख्या में स्कूल व कालेज नहीं हैं, जो हैं भी वहां भी धांधली चलती रहती है । फीसें इतनी ज्यादा हैं कि गरीब विद्यार्थी वहां पढ़ नहीं सकते । जिस प्रकार मकानों के भाड़ों एवं अन्य चीजों के मूल्यों पर रोक लगायी जाती है उसी प्रकार शिक्षण-संस्थाओं में फीस की भी एक सीमा कानून द्वारा निर्धारित करें और जो स्कूल उस सीमा से ज्यादा फीस लगावें उनको सरकार मान्यता न दे । जहां-जहां स्कूल व कालेज नहीं हैं वहां-वहां उनकी स्थापना करें ।

एक बात मैं आपके द्वारा और निवेदन करना चाहता हूं। यहां से विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिये विदेशों में विदेशी मुद्रा खर्च कर के भेजा जाता है जिसकी यहां कमी है । ये छात्र वहीं रह जाते हैं। इसके कारणों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये । उन विद्यार्थियों को यहां आने पर उनकी आवश्यकता व योग्यता के आधार पर पारिश्रमिक ठीक नहीं मिलता एवं अन्य सुविधायें भी पूरी नहीं मिलतीं जब कि विदेशों में उन्हें बहुत सी सुविधायें मिलती हैं जिसके कारण वे वहीं रह जाते हैं। इस पर भी हमारे शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिये और ऐसी योजना बनानी चाहिये जिससे यहां के होनहार विद्यार्थी विदेशों में ही न रह जावें बल्कि यहां आ कर अपने देश का लाभ करें ।

स्त्री शिक्षा की भी बहुत कमी है। जब तक हम अपनी बालिकाओं की शिक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं कर सकेंगे तब तक हमारा काम अधूरा ही रहेगा । आज भी भारतवर्ष में स्त्री शिक्षा न होने के कारण बहुत ही रूढ़ियां चल रही हैं । हमारे यहां पर्दा प्रथा चल रही है, उसे दूर करना जरूरी है । इसे हटाये बिना ज्यादा प्रगति नहीं हो सकती ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां आबादी दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है । इसे भी रोकने की जरूरत है जिसके लिये हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जिनके दो बच्चे हो जावें उनका आपरेशन कराना अनिवार्य हो । हमारी माताओं को यह समझाने की जरूरत है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से शारीरिक स्वास्थ्य तो नष्ट होता ही है उसके साथ-साथ ज्यादा परिवार होने से उनकी पूरी देखभाल भी नहीं हो सकती । इसका फल उन्हें ही भोगना पड़ता है । सिर्फ यह कह देने से काम नहीं चल सकता कि हम क्या करें बच्चे

[श्री आर० पी० खेतान]

तो ईश्वर की मर्जी है । हम जब तक जनता की आबादी में जो बढ़ती हो रही है उसको रोक नहीं सकेंगे तब तक कोई भी योजना सफल नहीं होगी । इसलिये इस बारे में ध्यान देना निहायत जरूरी है ।

हमारे यहां आर्थिक प्रगति में बहुत सी बाधायें कानून द्वारा डाल दी गई हैं जिनके रहते हुए उद्योगधंधे नहीं बढ़ सकते । लाइसेंस देने में भी इतना समय ले लेते हैं जिससे कि समय पर उद्योग नहीं बैठ पाता । यह लाइसेंस सिस्टम ही हटा दिया जाना चाहिये । अगर कुछ धंधों में कंट्रोल रखना जरूरी है जिनमें कि विदेशी मुद्रा लगती हो तो उनके बारे में भी जल्दी ही निर्णय लेना चाहिये ।

हमारे यहां करों की इतनी भरमार है कि लोगों को नये-नये उद्योग धंधे स्थापित करने का उत्साह नहीं रह गया है । हमें करों की दरों को घटाना चाहिये । सेल्स टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स जो लगाये जाते हैं वे अगर उत्पादकों और आयातकर्ताओं पर पहले ही लगा दिये जावें तो सरकार को भी पूरा राजस्व मिलेगा और लोग भी हैरानी से बच सकेंगे । इसके रहते बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है । यह तथ्य है कि सेल्स टैक्स के कारण लोग बिना कैश मीमो के ही चीजें खरीद-बिक्री करते हैं और यह धंधा बहुत जोरों से देश में चलता है । इससे सिर्फ सेल्स टैक्स ही कम नहीं मिलता किन्तु इंकमटैक्स पर भी इसका असर पड़ता है । अगर सरकार सेल्स टैक्सों को ऐट सोर्स कर दे तो भ्रष्टाचार में कमी आवेगी । मैं जानता हूं कि इसे प्रान्तीय सरकारें नहीं चाहेंगी क्योंकि उनके भ्रष्टाचार अधिकारीगण इसे नहीं चाहते हैं मगर केन्द्रीय सरकार इसे ध्यान में ले तो यह काम हो सकेगा ।

आडिट रिपोर्ट (सिविल) आन रेवेन्यु रिसीट के पेज 43 को देखने से पता चलता है कि अधिकारियों की भूलों के कारण 8 करोड़ 65 लाख रु० का असेसमेंट कम किया गया है । यह तो कुछ टेस्ट केसों में है, हो सकता है कि और भी भूलें हों । सुना जाता है कि अधिकारियों के पास ज्यादा असेसमेंट फाइलें दे दी जाती हैं जिससे कि ये भूलें होती हैं । मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि अगर वे इंकमटैक्स में जो चार हजार रु० की छूट आमदनी पर दी है वह यदि बढ़ा कर छः हजार तक कर दी जावे तो करीबन 4 लाख फाइलें कम हो जावेंगी जिससे कि अधिकारी लोग दूसरी फाइलों को ज्यादा ध्यान से देख सकेंगे और छूट देने के कारण से राजस्व में जो कमी होगी वह किसी प्रकार के नये करों के लगाये बिना ही पूर्ति हो जावेगी और कम आय वालों को राहत मिल जावेगी । इस महंगाई के समय में यह राहत काफी उन्हें मदद करेगी । मैं आशा करता हूं कि हमारे वित्त मंत्री इस पर ध्यान देंगे ।

SHRI P. C. MITRA (Bihar): Mr. Vice-Chairman, I rise to support the Arr'opria-tion (No. 2) Bill, 1966, as moved by the Minister of Slate of Finance, Shri Bhagat. Some hon. Members have raised controversies over the proposed Americf n participation in fertilizer projects and *i* lso the proposed Indo-U.S. Education Foundation. This morning the hon. Minister of Petroleum and Chemicals has made the necessary clarifications about the fertilizer projects and I would, not deal mveh with that matter. In regard to the Indo-U.S. Education Foundation, the Prime Minister has rightly pointed out in a press conference that under the existing agreement the United States Government have practically full discretion to utilise the PL 480 funds accumulated in India subject to the condition that the utilisation should not be detrimental to the interests of the people of India. The change is only to the extent that they want Government of India's participation in spending part of the large funds so accumulated in their account. It has been made clear that the fvnds of this Foundation shall be utilised for scientific and technical education, and naturally some American technicians and scientists will come to educate our students ;r.d ECEI I was not surprised when the first objee to the Foundation was raised by Communist

friends who are allergic to anything American though not averse to consumption of imported wheat from America. But I am really surprised when I find that some of my Congress colleagues in Parliament and a number of educationists also have ccme under the spell of the shallow Communis! propaganda. Their argument is that by such contacts the Americans may destrty our culture and our independent way of thinking. Many of these professors and Members of Parliament have got some education in either the U.K. or U.S.A. Shri Bhupesh Gupta, the hon. Communist leader of the House, also got part of his education in London. If they have not lost their independence of thought, then why have they got such a poor opinion of our present students and scholars that they will lose their independence of thought and culu they come in contact with the American scientists and technicians? In my opinion, this hue and cry among the intellectuals has been raised by vested interests who lu;ve got the means to send their sons and daughters to the US or to the UK for higher scientific studies. They find that their advantage of means is likely to be affected as meritorious students of moderate means will get higher scientific education in the country if scientific knowledge of America comes here through this Foundation.

In regard to US participation in the fertiliser pre jscts, it is argued that it goes against our Industrial Policy Resolution and our socialist objective. Even for argument's sake, if we accept their contention for a moment, the main consideration before us is whether there is any immediate possibility of getting any alternative source that will make India self-sufficient in fertilisers. If that is not so, then food production is more urgent than even deviation from the Industrial Policy Resolution.

In regard to the socialist objective, why should persons having faith in the ultimate victory of socialism be so chicken-hearted as to believe that contact of some scientific experts will cause the people to deviate from the socialist ideology? Why do we want to establish a socialist society? It is because we believe that the colossal poverty of the masses cannot be eradicated without establishing a socialist society. Incidentally, I would lik to ask my friends who genuinely want to establish a socialist society whether there is any possibility of ushering in a socialist society in India without curtailing fundamental rights granted under otr Constitution? In my opinion, even if the Communist Party comes into power in India, they cannot establish a socialist society keeping intact the fundamental rights of the people granted under the Constitution and free judiciary. I think they should prove into this matter and find out whether we require any amendment of theCcnstituticn. Under the democratic system that we are rightly following, wc must admit that our socialism will not be more progressive than of the British Labour Party. If the British Labour Government can nationalise the steel industry in spite of rebuilding their shattered economy after having received huge aid under the Marshall Aid and the American aid, that will not prevent us from getting American aid for the fertiliser industry to make the country socialistic.

In the Appropriation Bill, about Rs. 968 crores have been provided for deft nee expenditure. There is hardly any objection from any quarter for this heavy expenditure over the defence of the country. The only objection is that the Government gives too much importance to things which are taken to be—obsolete in the modern system of defence. It is really unfortunate that our Government does not beccme wiser by one event. When in 1962 the Chinese used automatic rifles then our Government decided to manufacture automatic rifles. Now they are waiting to be attacked by China or Pakistan by nuclear bombs and then only their underlying faith that China is making itself equipped with nuclear weapons to fight America and not us, will go and they will start preparing nuclear bombs. They do not realise that for the maintenance of world peace nuclear weapons are necessary. The US and the USSR have come nearer to each other only when both have realised that the one has got the capacity to destroy completely the other's cities and factories by nuclear bombs or missiles. Talking of peace is very easy; but maintenance of peace is a hard job.

I would like to say a few words about our foreign relations, particularly as to what shall be our basic approach. In my opinion the only approach shall be national interest consistent with our self-respect and dignity. We find how Russia and China, two

[Shri P. C. Mitra] Communist countries, aic courting Pakistan and the UAR, though both the latter Governments are openly anti-Communist. Similarly, democratic UK and France are trying to improve their relations with China. We claim that we follow an independent foreign policy but in fact we consider sentiments and susceptibilities of many other countries. While West Germany had no consideration for the reactions of the Arab countries and recognised East Germany, we are afraid to offend West Germany and so do not recognise East Germany. Similarly, the UAR has very friendly relations with Soviet Russia though the latter country has very friendly relations with Israel. We are afraid that our friendly relations with the UAR will be jeopardised if we recognise Israel which country is eager to have full diplomatic relations with our country. Israel has done nothing against our national interests while some of the Arab countries confronting Israel have definitely acted against our interests and helped our enemy, Pakistan. I would ask the Government whether any other country in the world would give any consideration to our sentiments in the question of opening diplomatic relations with any other country? Or is this only an one-sided affair? The sooner we rid ourselves of such inhibitions, the better it is for our national interest.

One thing more. It is an accepted convention in the foreign policy of each country to retaliate when any country does anything hostile to that country. Pakistan, a small country, closed the American monitoring bases when America suspended the supply of free gifts of American military hardware during the Indo-Pakistan conflict. But we came to new trade agreements with certain Arab countries after they openly sided with Pakistan during the Indo-Pakistan conflict. Have we got the courage to frankly state to the USA that in case of resumption of military aid to Pakistan we shall try to counteract the move by coming nearer to Soviet Russia for the maintenace of our sovereignty and independence? Such frank talks will give us dividend and increase the country's moral strength.

I am glad that the Government is considering the suggestion of scrapping the Gold Control Order. This control has not served the purpose but has forced many people who otherwise are very law-abiding, to connive at the illegal transactions of the goldsmiths. Had the Govei nment taken care to find out how many marriages during the last three, years have been performed without any gold ornaments? 1 am afraid, if any such prove is made, the result will be nil or may be counted on one's fingers. We must have the courage to scrap any law if it is proved that that law has not served the purpose for which it was enacted.

I would suggest that on the same ground partial prohibition in the country should also go.

I would like to say something about the Naga and Mizo menace. In 1961 I had asked in this House a question and I propagated the view that we should give the Army full control and freedom to take action against the Nagas, and some other Members objected to my proposition at that time. But now after five years many are coming round to the position that vc ought to have done it. Even if a strike is launched by a small group of workers or by teachers or by students even, the Government says that it will not come to any negotiation with them unless they withdraw their strike. But here the Nagas continue their massacre of innocent lives and loot property for two years but we are continuing negotiations with them and not even once have they come to an agreement with the Government's or the Peace Mission's proposat that they should remain within India, that they should voluntarily accept to remain within India. Still we hope against hope that ultimately we can solve this Naga problem peacefully. Sir, when we have the responsibility of governing the country, then we should actually behave ourselves as a responsible Government.

The Government has the first task not only of saving the country from external dangers but also from internal dangers. And this danger is manifested in this Naga and Mizo menace. Now the Nagas and Mizos want to combine with China and Pakistan to turn the eastern India into a Vietnam. Therefore, in my opinion, the Government should take speedy steps so that the whole matter should be reviewed again and this Naga and Mizo menace is crushed for good.

SHRI R. S. KHANDEKAR (Madhya Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, today

our country is facing the twin problems of defence and development. As far as defence is concerned, we tincl that the Tashkent spirit which was created some time back is slowly receding. When the Tashkent Agreement was signed, we were one of those who had opposed the Declaration and had warned that after so much experience vfe should learn something. But, unfortunate!) do not learn from history. We are having the spectacle of Pakistan and China joining together and Pakistan having cold against us. In the Spirit of Tashkent we lost whatever we had won in the war. Similarly, there are alarming reports of heavy concentration of Chinese troops all along our border. Therefore, there is a great need of vigilance and preparedness so far as the defence of the country is concerned.

At the same time we have got a long border on the sea side and our Navy is not veil equipped to defend our country. We have some experience. Last lime we had an opportunity to visit some of the parts and we saw some of (he war ships. We were told that one or two ships will not be sufficient to protect such a long border, Therefore, my submission is that we must have many more fighter ships like l.N.S. Vtkrant all along the border, in the West and in the East also.

Coming to the internal problem, there is a sort of anarchy in our country. We sec the spectacle of the Central Government going one way and the State Chief Ministers going the other way. I can recount a numbei of instances where the centre has been found weak and the Chief Ministers have dominated the Central Government. Only today I had tabled a question about the abolition of the post of B.D.O.s in our Stale. 1 do not hold any brief for the B.D.Os, whether they should he retained or thej should be dispensed with. But before taking this salutary step unilaterally, the State Government should have asked the Central Government. I am told the Central Government was never in favour of abolishing these posts. When the State Chief Ministet took this decision unilaterally, it was defended and the Central Government was a helpless spectator to thai development. Questions were raised and the Central Government said that they had appointed a committee and were finding out whether M50RS/66—6 this abolition of posts had helped or had not helped. 1 had asked a question about the findings of the Committee, and here is atement by the Minister. It is a very revealing statement. 1 would not take your time in reading all the items, but I would draw your attention to only certain things. The first thing they have said:

"The field work of the Agricultural Extension Officer, who has been made the drawing and disbursing officer of the block, has suffered consequent on the added work given to him with the abolition of the posts *of* Block Development Office That means the work has suffered;

"((/') There is no single oilicer at the block level who can get an overall view of the various aspects of development,

"(Hi) Since eases of loans and grants, which were earlier disposed of by the B.D.O. under the powers delegated to him, have to go to the Sub-Division Office the Collector, tl. ope for further delay in the disposal of such cases.

l'he Sub-Divisional Officer been placed in charge of coordination work in all the block in his jurisdiction. The work load is heavy for effective performance of the functions.

"(v) With the abolition oftheB.D.O's post, the responsibility of the district level technical officer has increased; he has not only to provide technical guidance to the Extension Officer as hitherto, but has to attend to matters of coordination at the local level."

So with regard to this there is ample proof that the Central Government cannot do anything.

With regard to the lifting of the emergency, we have seen that even though the Central Government wants to lift the emergency, these State masters do not want it because with the help of this emergency and D.I.R. they want to control the administration at the point of the bayonet.

With regard to prohibition, we all know that certain Stales are in favour of abolition of prohibition whereas the Central Government wants prohibition to stay, but the State Governments are unilaterally going (o lift

prohibition in their States. There are various other instances which I will not recount.

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

Now, Madam, the internal situation in this country is alarming. When I say this, I mean that the law and order situation in r«spect of States is not satisfactory. It is so particularly with our State. The State is being ruled at the point of the bayonet and with the help of the police. Madam, you are aware that our State, particularly the northern part of it, is infested with dacoits, and whatever the credit the State Government may take for the abolition of the dacoit menace, the fact is that the dacoits have not been liquidated. On the contrary, they are on the increase. Recently there was a case where in the name of harbouring dacoits the police in day time entered the house of a respectable person who is a Congressman. The police began to abuse him. The only fault of that person was that he could not stand up and salute the police officer. So he began to beat him. When his sons and nephews intervened, because he was being unnecessarily beaten the police officer got enraged and asked the policemen to shoot down the nephews and sons. When one of them was fired upon, he ran out and behind him ran the others. On the plea that they were being encircled, the police officer ordered firing and subsequently two people died and three were seriously wounded. They are now in the hospital.

It is most surprising that the press is also not free. The press reported the incident saying that about 100 people had gathered there to 6ave the dacoit who was being given shelter there and the police has to open fire and consequently these two people died. But when we went there, we found that there was not a place for more than 10 people to stand where this incident took place. The Government have ordered only a magisterial enquiry; he is a puppet of the Government. I sent telegrams to the Prime Minister, the Home Minister and to our Chief Minister but I have not received even the acknowledgement so far. They do not reply even to telegrams, much less to letters or communications. Then there was a lot of agitation by all political parties but nothing has been done. The police officers who ordered these shootings are still there and are trying to suppress the evidence. They are also trying to issue charge-sheets against those persons who have been killed or wounded under section 307 *i.e.* they have tried to murder the police. The challans are now ready. The poor fellows got killed there and those who have survived are now facing the murder charge.

As far as Bastar is concerned, I need not repeat all that has happened. A lot of discussion took place. What was the demand of the Opposition? It was that those officers who were involved in this brutal crime should be transferred from that district but nothing has been done as yet. How can you expect any judicial enquiry when those officers are still there? When the order under section 144 is there, nobody can give any evidence. Still the Government says that the Enquiry Commission is there and justice will be done. We only want that justice should appear to have been done. If there are any doubts, you should try to remove them. We do not want that the Judge who has been appointed should be removed. We want the enquiry Commission to be expanded and some outside judge may be associated with it so that there should be no room for doubts. But the Government has taken it as a prestige issue and in spite of so much opposition and so much protest it is not doing anything. How can Government talk of democracy when such undemocratic actions take place? How can a democratic rule be strengthened that way? Today only our Party organised a demonstration before the Parliament House. People came from Bastar, 1.000 miles away, only to request that justice should be done. In a democratic country when so much killing has been done, that Government has no moral right to exist. It has happened before. We have the instance of Kerala where firing took place and people died and that Government had to go. Previously in Madhya Bharat a Student demonstration took place. The police fired and two students died. One of the hon. Members of this House was the Chief Minister at that time. Naturally he had to quit. I can cite so many instances. When there is so much killing and unprovoked firing, that Government has no moral right to exist. Therefore the Central

Government must be more vigilant and they should not allow the State chiefs to act in whatsoever manner they like. This is the time for interfering in the Administration. I know that the reply would be that this is a Federation and certain powers have been defined. But at the same time this is a federal type of Government and the Centre has more responsibility. People in that district are panic-stricken and there is no normal life; it is only a police raj there. All the Parties and even the Congress Committees have passed resolutions and demanded fair and judicial enquiries but the Government is sitting tight over these things. Presumably the Chief Minister says that he has got a very strong support at the Centre and therefore nothing can be done against him. This is the impression that is created; we do not know the facts.

Since the time is very short, I would like to refer to two or three things in brief. With regard to food shortage a lot of discussion has taken place here and the Government says that no starvation deaths took place in this country. I cited one instance from my State, from the Bastar District that the adivasis there were dying of hunger and the people in Vindhya Pradesh were also dying of hunger. Adjournment motions were moved in the State Assembly but the same routine reply was given that no starvation deaths had taken place and those deaths were on account of either malnutrition or some disease. But it is forgotten that when a person eats leaves and roots and he does not get food, his power to live is reduced and ultimately he dies. It is very difficult to say where malnutrition ends and starvation begins. It is no use saying that there are no starvation deaths. The Government should admit frankly and if there are any such deaths, they should try to remedy the situation and provide food to them, not stand on a prestige issue.

With regard to the I. and B. Ministry. I have one word to say. The performance of this Ministry is far from satisfactory. This Ministry has not got even common knowledge with regard to M.P.s, their political affiliations and their activities. They often misquote and mispronounce the names or wrongly associate those Members. I have written a letter to the A.I.R. The Director-General has regretted the mistake but this regret is not enough because afterwards also these mistakes have continued.

With regard to the proceedings of this House also, the A.I.R. does not give as much importance as should be given. I have no quarrel with the A.I.R. if it gives more importance to the other House, but when some important discussions take place in this House, the A.I.R. should take cognisance of this House.

Lastly, Madam, I would repeat that the country is in a very difficult position internally as well as externally. So the Central Government should be strong enough and dedicated enough. They should rise above party lines and try to ssve and strengthen democracy in this country; otherwise the future will be very dark for us.

4 P.M.

STATEMENT BY MINISTER *RE* LIBERALISATION OF INDUSTRIAL LICENSING POLICY

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI D. SANJIVAYYA): Madam, as the House is aware, both in this House and outside leaders of public opinion belonging not only to the Congress party but also to some other parties, have from time to time, suggested the need for a review of the continuance of various controls in the economic field. The Prime Minister has also one more than one occasion, recently reiterated Government's policy that controls would be maintained only where it is necessary in the public interest to do so. Government have been therefore keeping under review the various controls in existence.

2. As regards the specific control relatin? to the licensing of industries under Industries (Development and Regulati'o Act, 1961, over the past two years Government have announced some relaxations. All industries with fixed assets not exceeding Rs. 25 lakhs were exempted from the licensing provisions of the Act in 1964. Some relaxations regarding diversification of production by manufacture of 'new articles' by existing units and relating to 'substantial expansion' of the licensed •apacity in cases not involving any foreign exchange expenditure were announced last year. The possibiliiy of making further relaxations has been under Government's consideration for some time.